For Restricted Use Only

आज़ादी का अमृत महोत्सव

"Eradicate Corruption –
Way to Developed Nation"

VIGILANCE DEPARTMENT

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

VISION

A world class energy entity with commitment to environment and social values.

MISSION

- To plan, develop and operate energy resources efficiently.
- To adopt state of the art technologies.
- To achieve performance excellence by fostering work ethos of learning and innovation.
- To build sustainable value-based relationship with stakeholders through mutual trust.
- To undertake rehabilitation and resettlement of project affected persons with human face.

VALUES

- Zeal to excel and zest for change.
- Integrity and fairness in all matters.
- Respect for dignity and potential of individuals.
- Ensure speed of response.
- Strict adherence to commitments.
- Foster learning, creativity and team work.
- Loyalty & pride in CPSE.

सत्यमेव जयते

राष्ट्रपति
भारत गणतंत्र
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA

MESSAGE

I am pleased to know that the Central Vigilance Commission is observing Vigilance Awareness Week, 2022 from 31st October to 6th November, 2022 on the theme:

"भ्रष्टाचार मुक्त भारत - विकसित भारत"
"Corruption free India for a developed Nation"

The fight against corruption is the collective duty and responsibility of all the citizens of this great nation. The ideals of transparency and integrity are an integral part of our tradition and culture. A corruption free India is the vision shared by all of us as we progress towards a new and developed India. We need to reiterate the ideals of integrity and accountability and strive towards embracing the values that have guided us in our journey so far.

On this occasion, I commend the Central Vigilance Commission for its efforts in combating corruption and convey my best wishes for the success of Vigilance Awareness Week 2022.

(Droupadi Murmu)

New Delhi
October 11, 2022

सत्यमेव जयते

भारत के उपराष्ट्रपति
VICE-PRESIDENT OF INDIA

MESSAGE

I am pleased to know that the Central Vigilance Commission is observing Vigilance Awareness Week, 2022 from 31st October to 6th November, 2022 with the following Theme:

"भ्रष्टाचार मुक्त भारत - विकसित भारत"

"Corruption free India for a developed Nation"

Transparency, fairness and accountability are essential values for the efficient functioning of the public administration. It is the responsibility of the all the citizens of the country to come together in the efforts to ensure integrity in governance. This year, the Central Vigilance Commission have also undertaken a three-month campaign on preventive vigilance measures. I hope to see all citizens and stake holders collectively participate in large numbers in the fight against corruption.

On this occasion, I commend the Central Vigilance Commission for their efforts in combating corruption and convey my best wishes for the success of Vigilance Awareness Week 2022.

Jagdeep Dhankhar

New Delhi
6th October, 2022

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री
Prime Minister

संदेश

केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 31 अक्टूबर से 06 नवंबर, 2022 के बीच सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई है। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह के लिए 'भ्रष्टाचार मुक्त भारत- विकसित भारत' विषय का चयन सराहनीय है।

भ्रष्टाचार न केवल सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित करता है बल्कि देश की प्रगति में अवरोध भी उत्पन्न करता है, और एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिकता की शक्ति को प्रभावित करता है। बीते आठ वर्षों में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं, जहां यह संदेश स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह देश में विश्वास का एक वातावरण उत्पन्न हुआ है, जिसमें हर ईमानदार व्यक्ति आज खुद पर गर्व महसूस करता है।

भ्रष्टाचार को मूल से उखाड़ फेकने के लिए पूरी प्रक्रिया, पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जा रहा है। तकनीक और रिफॉर्म्स के जरिए व्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा रही है ताकि न केवल आज, बल्कि भविष्य में भी किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे और नागरिकों का हित सुरक्षित रहे।

यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस वर्ष आयोग द्वारा निवारक सतर्कता उपायों पर तीन महीने का एक अभियान भी चलाया जा रहा है। कहा गया है- **'प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूरात् स्पर्शनम् वरम्।'** अर्थात, गंदगी लग जाए फिर उसे साफ करो, इससे अच्छा है कि गंदगी लगने ही न दो। जिन परिस्थितियों की वजह से भ्रष्टाचार पनपता है, हमारे लिए उन पर प्रहार करना आवश्यक है।

आजादी के अगले 25 वर्षों की यात्रा एक भव्य और विकसित भारत के निर्माण में हम सभी का कर्तव्य काल है। यह अवसर एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपने प्रयासों में तेजी लाने का है। मुझे विश्वास है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन जीवन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को बढ़ावा देकर राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे संकल्पों को मजबूती प्रदान करेगा।

केंद्रीय सतर्कता आयोग को आयोजन की सफलता और भविष्य के प्रयासों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

(नरेन्द्र मोदी)

नई दिल्ली
कार्तिक 05, शक संवत् 1944
27 अक्टूबर, 2022

अमित शाह

सत्यमेव जयते

गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मजयंती सप्ताह में **31 अक्टूबर से 06 नवम्बर, 2022** तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह-2022 का आयोजन **'भ्रष्टाचार मुक्त भारत-विकसित भारत'** थीम पर किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराई का सामना करने के लिए, देश के नागरिक के रूप में हम सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। यह हमारा कर्तव्य और उत्तरदायित्व है कि हम देश के विकास में योगदान दें तथा भ्रष्टाचार का विरोध करके राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संदेश को आगे बढ़ाने में कई प्रभावी कदम उठाए हैं। निवारक सतर्कता उपायों पर तीन महीने का एक अभियान भी चलाया है। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाने हेतु विभिन्न गतिविधियां आरंभ की गई हैं, जो सराहनीय है।

माननीय प्रधानमंत्री **श्री नरेन्द्र मोदी जी** ने **'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास'** के मूल मंत्र के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा दिखाए मार्ग पर चलकर शासन व्यवस्था में एक ऐसे बदलाव की शुरुआत की है, जो सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के पथ पर अग्रसर है। सरकार की नीतियों में गरीब कल्याण के प्रति चिंता और अंत्योदय का भाव स्पष्ट नज़र आता है। सामान्य जन-मानस के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। आज विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नागरिकों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने एवं उन्हें सामाजिक-आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने का सफल प्रयास किया जा रहा है।

मैं, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सभी पदाधिकारियों को उनके भावी प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए, सतर्कता जागरुकता सप्ताह-2022 के सफल आयोजन की कामना करता हूँ।

(अमित शाह)

श्री सुरेश पटेल,
केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

कार्यालय : गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 23092462, 23094686, फैक्स : 23094221

राजनाथ सिंह
RAJNATH SINGH

सत्यमेव जयते

रक्षा मंत्री
भारत
DEFENCE MINISTER
INDIA

MESSAGE

I am happy to note that Central Vigilance Commission has chosen "Corruption Free India for a Developed Nation" as a theme for current year's Vigilance Awareness Week (31st October to 6th November), organized every year in the week coinciding with birthday of Baharat Ratna Sardar Vallabhbhai Patel.

During Vigilance Awareness Week, the Commission solicits the participation of the citizens of India through various programmes such as Gram Sabhas, Lectures, Competitions, etc. Schools, Colleges, Trade unions, etc. are also encouraged to participate in various programmes.

I convey my best wishes to Central Vigilance Commission for choosing the theme "Corruption Free India for a Developed Nation" we the people of India, must imbibe a sense of ethics and integrity in all aspects of their everyday life to make India a developed nation.

"Jai Hind"

(Rajnath Singh)

Place: New Delhi
Date: 14th Oct, 2022

Office : Room No. 104, Ministry of Defence, South Block, New Delhi-110011
Tel. : +91 11 23012286, +91 11 23019030, Fax : +91 11 23015403
E-mail : rmo@mod.nic.in

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स,
ब्लॉक–ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-10023

सं. / No. 022/VGL/029(Pt.II)

दिनांक / Dated 19.10.2022

MESSAGE

Central Vigilance Commission observes Vigilance Awareness Week every year in the week in which the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel falls. It is our pleasure to announce that Vigilance Awareness Week, 2022 is being observed from **31st October to 6th November, 2022** with the following theme:

"भ्रष्टाचार मुक्त भारत - विकसित भारत"

"Corruption free India for a developed Nation"

As we progress in the journey towards growth and development, there is an ever-growing need for transparency and integrity in public administration. It is the collective duty and responsibility of all citizens to fight corruption and build a strong and ethical India. As a precursor to Vigilance Awareness Week 2022, Central Vigilance Commission has undertaken a three-month campaign (16th August to 15th November) in which six different preventive vigilance measures were taken up as focus areas by different organizations.

Children are the future of the country, and they would play a key role in building our nation. Keeping this in mind, we have also held an essay competition on this year's theme wherein there was enthusiastic participation of students. More than 7.6 lakh students of Class X, XI and XII studying in over ten thousand CBSE schools across the country have taken part and expressed their views on the subject.

The Commission appeals to all citizens to come together to reaffirm our commitment to bring about integrity in all aspects of life for the Nation's development.

19.X.22
(Arvinda Kumar)
Vigilance Commissioner

(Praveen K. Srivastava)
Vigilance Commissioner

(Suresh N. Patel) 19/10/2022
Central Vigilance Commissioner

Rajeev Kumar Vishnoi
Chairman & Managing Director
THDC India Limited

FOREWORD

I am extremely delighted to note that Vigilance Department is observing"Vigilance Awareness Week-2022" from 31st October to 06th November, 2022.The theme for Vigilance Awareness Week-2022 as given by CVC is **"भ्रष्टाचार मुक्त भारत–विकसित भारत" (Corruption free India for developed Nation)**.It is an extremely apt topic in today's context when the whole nation is celebrating Azadi ka Amrit Mahotsav and moving rapidly towards Corruption Free India to make best efforts to enhance the Economy despite the fact that the Indian and the global economy has been affected adversely by the Covid-19 pandemic and more recently by the Russia-Ukraine war.

On this occasion, Vigilance department is coming out with a new edition of Vigilance Booklet **"Eradicate Corruption - Way to Developed Nation"**consisting of latest CVC's circulars, various Systemic Improvements suggested by Vigilance Department, new articles/poems from field executives & officials etc. This booklet will provide a platform to create awareness amongst officials. As it is evident from the contents, the main motive of Vigilance Department is to lay stress on the efficacy of preventive vigilance in system improvement, curbing corruption to accomplish the organizational goals collaboratively and maintaining a sense of transparency and accountability across departments.

Vigilance Awareness Week gives us an opportunity to re-dedicate ourselves to eradicate corruption from society and reinforce the fact that the "Honesty is the best Policy". In THDC India Limited, we are devoted to ensure implementation and adoption of highest standards of corporate governance. Participation of each employee of the organization with ethics is utmost important in realizing the vision of New India.

I would expect that each employee of the organization would adhere to the principles and values enshrined in the ethics policy of the organization. If each of the employees of the organization contributes gainfully with honesty & sincerity towards the organization, then such an organization becomes collective strength of the "Developed Nation". The philosophies of honesty, integrity, transparency, fairness, and righteous action are the guiding lights for an efficient and effective governance.

I appreciate the efforts of Vigilance Department for issuing System Improvements during whole year and getting this book published. On this occasion I extend my best wishes for successful celebration of Vigilance Awareness Week -2022.

Place: Rishikesh
Date: 18 Oct. 2022

18/X/2022
(R. K. Vishnoi)

प्रेम प्रकाश, आईओएफएस
मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रस्तावना

केंद्रीय सतर्कता आयोग, भ्रष्टाचार से लड़ने और सतर्कता प्रशासन पर सामान्य अधीक्षण करने हेतु जनादेश युक्त सर्वोच्च संस्थान है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह, भ्रष्टाचार के खतरों के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोग द्वारा अपनाए गए विभिन्न प्रभावी उपायों में से एक है।

सतर्कता विभाग का यह सतत एवं प्रतिबद्ध प्रयास है कि पूरे संगठन को केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा विहित उद्देश्यों को पाने की ओर उन्मुख किया जाऐ। सतर्कता जागरूकता सप्ताह, हमें उन जिम्मेदारियों और आदर्शों की याद दिलाता है जो भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है,मसलन-सत्यनिष्ठा,पारदर्शिता और जवाबदेही। हम इस वर्ष 31 अक्टूबर'22 से 6 नवंबर'22 तक "भ्रष्टाचार मुक्त भारत-विकसित भारत"(Corruption Free India for a Developed Nation) विषय को केन्द्रित कर, सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं।

भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण और सुशासन विकसित राष्ट्र की प्रमुख विशेषता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान सिर्फ एक दिन या सिर्फ एक सप्ताह का मामला नहीं है। जागरूकता पैदा करने के लिए संगठन के प्रत्येक कर्मचारी की पूर्ण भागीदारी, हर वक़्त भ्रष्टाचार विरोधी सदप्रयास निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मुक्त संगठन का निर्माण कर पायेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त देश और समाज को बनाने के लिए हम सभी को ईमानदारी और नैतिकता का भावनात्मक और संरचनात्मक ढांचा तैयार करना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीतियों और उसके क्रियान्वयन का आधार ही सत्यनिष्ठा और नैतिकता होनी चाहिए। भ्रष्टाचार से निपटने और भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सूचना प्रोद्यौगिकी और आधुनिक तकनीक का उत्तरोत्तर प्रयोग किये जाने की भी आवश्यकता है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर, सतर्कता विभाग, समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिये"**Eradicate Corruption-Way to Developed Nation**" नामक एक पुस्तिका प्रकाशित कर रहा है। यह पुस्तिका, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों और परिपत्रों के साथ साथ सतर्कता विभाग द्वारा जारी किए गए कुछ प्रणालीगत सुधारों एवं प्रासंगिक लेखों/रचनाओं का संग्रह है। उम्मीद है कि यह टीएचडीसीआईएल में सभी के लिए एक बेहतर सन्दर्भ पुस्तिका साबित होगी एवं कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों से परिचित कराने में बेहद सहायक होगी।

आइए, हम सब हाथ मिलाएं और जीवन के सभी क्षेत्रों से भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए अनवरत प्रयास करने का संकल्प लें।

दिनांक : 18.10.2022

(प्रेम प्रकाश)

उद्घोषणा

यह बुकलेट सामान्य मार्गदर्गन के उद्देश्य से प्रकाशित की गयी है एवं केवल सरकारी उपयोग के लिए है। इसे न तो किसी सरकारी सन्दर्भ में उपयोग किया जाए और न ही साक्ष्य हेतु न्यायालय में पेश किया जा सकता है। जहां कहीं इसका सन्दर्भ देना आवश्यक हो, उस विषय से सम्बंधित मूल आदेशों का ही दिया जाए।

DISCLAIMER

This booklet is purely for the purpose of providing guidelines and is intended for official use only and should not be quoted as authority in any official reference or produced in a Court. A reference, whenever necessary, should always be made to the original orders on the subject.

CONTENTS

SL. NO.	SUBJECT	PAGE NO.
PART-I	**RECENT CVC CIRCULARS**	
1.	Timely finalization of Departmental Inquiry Proceedings-improving vigilance administration. - dtd.- 03.12.2021.	14
2.	Timely finalization of Departmental Inquiry Proceedings-improving vigilance administration. - dtd.- 08.12.2021.	16
3.	Procedure for seeking Commission advice in cases where CBI has recommended sanction for prosecution. - dtd.- 21.01.2022.	19
4.	Transfer/posting of officers/officials working in Vigilance unit of the organizations. - dtd.- 03.02.2022.	21
5.	Procedure for Handling of complaints sent for necessary action to the organization concerned. - dtd.- 11.02.2022.	24
6.	Revised Proforma for furnishing details of officers by the Cadre Controlling Authorities while seeking vigilance clearance-modification of point no.13. - dtd.- 16.03.2022.	27
7.	Confirmation on Timely submission of Annual Immovable Property Return (AIPR) in the proposals seeking input of the commission on vigilance status of officers for empanelment. - dtd.- 16.03.2022.	31
8.	Implementation of final penalty orders issued by the Competent Authority and submission of compliance report. - dtd.- 21.03.2022.	33
9.	Updation of Manual on Procurement of Goods, Services, Works and Consultancy etc. - dtd.- 11.07.2022.	36
10.	Intimation to CVC & CBI in cases pending for sanction for prosecution. - dtd.- 29.07.2022.	39
11.	Uploading of Commission's Circulars/Guidelines, subsequent to release of Vigilance Manual-2021. - dtd.- 29.08.2022.	40
12.	Clarification regarding the enquiry/investigation to be conducted against officers on deputation. - dtd.- 01.09.2022.	42

PART-II	**SYSTEMIC IMPROVEMENTS SUGGESTED BY VIGILANCE DEPARTMENT**	
1.	Systemic Improvement with regard to preparation and checking of the Estimates	46
2.	अचल संपत्ति विवरण के संबंध में (प्रणालीगत सुधारात्मक परिपत्र)	47
3.	Systemic Improvement with regard to Purchase through committee.	48
4.	Systemic Improvement with regard to % age Checking/Verification of measurements in MB by executives of Execution Deptt.	49
5.	Standard guidelines for contractor profit/Overheads considered in manpower engagement works and its applicability on EPF, ESI, hidden charges etc.	50
6.	Systemic Improvement with regard to Proprietary Article Certificate (PAC)	51
PART-III	लेख / कविताएँ	
1.	Corruption Free India for a Developed Nation.	54
2.	क्या फ़र्क पड़ता है।	55
3.	भ्रष्ट्राचार मुक्त भारत हेतु प्रयास-विकसित भारत-एक परिणाम।	56
4.	ईमानदारी।	57
5.	भारत में भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी : एक पुनरावलोकन।	58
6.	"भ्रष्टाचार मुक्त भारत - विकसित भारत"।	60
7.	परिवार से परिवर्तन।	61
8.	भ्रष्टाचार मुक्त भविष्य।	62
9.	भ्रष्टाचार मुक्त विकसित भारत: एक सोच बदलाव की।	63
10.	भ्रष्टाचार-मुक्त–भारत-विकसित भारत।	64
11.	खुदगर्जी।	65
12.	भ्रष्टाचार मुक्त भारत - समृद्ध भारत।	66
13.	भ्रष्टाचार मुक्त भारत।	67
14.	भ्रष्टाचार मुक्त भारत - विकसित भारत।	68
15.	भ्रष्टाचार मुक्त भारत-विकसित भारत।	69

सतर्कता जागरूकता सप्ताह
VIGILANCE AWARENESS WEEK

31st October - 06th November, 2022

''भ्रष्टाचार मुक्त भारत-विकसित भारत''

"Corruption free India for a developed Nation"

सतर्कता विभाग, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
Vigilance Department,THDC India Limited

PART-I

RECENT CVC CIRCULARS

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स,
ब्लॉक–ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-10023

सं./No. 000/VGL/018

दिनांक / Dated 03.12.2021

Circular No. 21/12/21

Subject:- **Timely finalization of Departmental Inquiry Proceedings -improving vigilance administration.**

Reference: -

(i) Commission's Circular No. 8(1)(g)/99(2)	**dated 19.02.1999**
(ii) Commission's Circular No. 8(1)(g)/99(3)	**dated 03.03.1999**
(iii) Commission's Circular No. 3(v)/99(7)	**dated 06.09.1999**
(iv) Commission's Circular No. 000/VGL/18	**dated 23.05.2000**
(v) Commission's Office Order No. 51/08/2004	**dated 10.08.2004**
(vi) Commission's Circular No. 02/01/2016	**dated 18.01.2016**
(vii) Commission's Circular No. 18/12/20	**dated 14.12.2020**
(viii) Commission's Circular No. 19/09/21	**dated 06.10.2021**

The Central Vigilance Commission, as part of its functions of exercising superintendence over vigilance administration of the organizations covered under its advisory jurisdiction has, time and again, laid emphasis on timely completion of disciplinary proceedings.

2. However, it has been observed that in cases where Regular Departmental Action for Major Penalty has been initiated, one of the main reasons for delay in completion of disciplinary proceedings is due to the delay caused in the inquiry proceedings being conducted by the Inquiry Officers. The Commission, vide its Circular dated 03.03.1999 had prescribed the model time limit for the Inquiry Officers for conducting departmental inquiries. The same was reiterated vide circular dated 18.01.2016. The Model time limit is again reproduced below:-

Stage of Departmental Inquiry	Time limit prescribed
• Fixing date of Preliminary Hearing and inspection of listed documents, submission of Defence Documents/witnesses and nomination of a Defence Assistant (DA) (if not already nominated)	Within four weeks from the date of appointment of Inquiry Officer.

• Inspection of relied upon documents/submission of list of Defence Witnesses/Defence Documents/Examination of relevancy of Defence Documents/ Defence Witnesses, procuring of additional documents and submission of certificates confirming inspection of additional documents by CO/DA • Issue of summons to the witnesses, fixing the date of Regular Hearing and arrangement for participation of witnesses in the Regular Hearing • Regular Hearing on Day to Day basis	3 months
• Submission of Writing Brief by PO to CO and IO	15 days
• Submission of Written Brief by CO to IO	15 days
• Submission of Inquiry Report from the date of receipt of Written Brief by PO/CO	30 days

3. The Commission has directed that the above time schedule should be brought to the notice of all Inquiry Officers (already appointed/to be appointed in future) for strict compliance.

4. The Commission has further directed that all the Inquiry Officers be asked to submit a monthly report to the Disciplinary Authority concerned, indicating the present status/progress of the inquiry proceedings being conducted by them. A copy of the monthly report should also be endorsed to the CVO of the organizations concerned, by the Inquiry Officer. In case, it is found that the inquiry proceedings are getting delayed beyond the prescribed time limit, the CVO concerned should immediately take up the matter with the Inquiry Officer and Disciplinary Authority concerned to ensure timely action.

5. The above instructions may be noted for strict compliance and may also be brought to the notice of all the Disciplinary Authorities and Inquiry Officers.

(Rajiv Verma)
Director

To

(i) The Secretaries of all Ministries/Departments of GoI
(ii) All Chief Executives of CPSUs/Public Sector Banks/Public Sector Insurance Companies/Autonomous Bodies etc.
(iii) All CVOs of Ministries/Departments of GoI/CPSUs/Public Sector Banks/Public Sector Insurance Companies/Autonomous Bodies etc.
(iv) Website of CVC

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स,
ब्लॉक–ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-10023

सं. / No. 000/VGL/018

दिनांक / Dated 08.12.2021

Circular No. 22/12/21

Subject:- Timely finalization of Departmental Inquiry Proceedings -improving vigilance administration.

Reference: -

(i) Commission's Circular No. 8(1)(g)/99(2)	dated 19.02.1999
(ii) Commission's Circular No. 8(1)(g)/99(3)	dated 03.03.1999
(iii) Commission's Circular No. 3(v)/99(7)	dated 06.09.1999
(iv) Commission's Circular No. 000/VGL/18	dated 23.05.2000
(v) Commission's Office Order No. 51/08/2004	dated 10.08.2004
(vi) Commission's Circular No. 02/01/2016	dated 18.01.2016
(vii) Commission's Circular No. 18/12/20	dated 14.12.2020
(viii) Commission's Circular No. 19/09/21	dated 06.10.2021
(ix) Commission's Circular No. 21/12/21	dated 03.12.2021

Attention is invited to Commission's Circular No. 21/12/21 dated 03.12.2021, vide which it was directed that Inquiry Officers, appointed by the organizations to conduct departmental inquiries, are required to submit a monthly report indicating present status/progress of the inquiries being conducted by them.

2. The Commission has desired that for the sake of uniformity and clarity, the information regarding the status of inquiry proceedings may be obtained from the Inquiry Officers, in the format as enclosed as **Annexure-I**, to this circular. The monthly report may be submitted by the Inquiry Officers, latest by 10th day of the succeeding month.

3. It may be noted that information should be obtained from the Inquiry Officers in respect of ongoing inquiries and also in respect of departmental inquiries, that may be instituted in future.

Contd...2...

4. The CVOs may bring the enclosed format to the notice of all the Disciplinary Authorities and Inquiry Officers for compliance of Commission's guidelines. issued vide Circular No. 21/12/21 dated 03.12.2021.

(Rajiv Verma)
Director

To

(i) The Secretaries of all Ministries/Departments of GoI
(ii) All Chief Executives of CPSUs/Public Sector Banks/Public Sector Insurance Companies/Autonomous Bodies etc.
(iii) All CVOs of Ministries/Departments of GoI/CPSUs/Public Sector Banks/Public Sector Insurance Companies/Autonomous Bodies etc.
(iv) Website of CVC

Name of Organization_____

Annexure-I

Name of Inquiry Officer_____ Report for the month of _____

S. No.	Name and Designation of CO	Date of appointment of IO	Date of Preliminary Hearing	Wehther Brief Hearing required. If Yes, date of Brief Hearing	No. of Regular Hearings held till the end of the month	Dates of Regular Hearing	Date of submission of PO's Brief	Date of submission of Defence Brief	Date of submission of IO's report	Time taken since appointment as IO (upto the stage inquiry has progressed so far)	Whether time limit given in Commission's Circular No. 21/12/21 dated 03.12.2021 is being adhered to. If not, reasons thereof
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Signature of Inquiry Officer

To,
Disciplinary Authority

Copy to:- Chief Vigilance Officer

Note:- Report to be submitted by IO by 10th day of every month to DA with copy to CVO.

आज़ादी का अमृत महोत्सव
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स,
ब्लॉक–ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-10023

सं. / No.....006/MSC/038.....

दिनांक / Dated....21.01.2022.....

Office Order No. 04/01/22

Subject: Procedure for seeking Commission advice in cases where CBI has recommended sanction for prosecution-regarding.

Reference:-
(i) CVC Office Memorandum No. 98/Misc/I dated 26.02.1999
(ii) CVC Office Memorandum No. 99/VGL/54 dated 08.08.2000
(iii) CVC Office Order No. 003/VGL/1 (Part) dated 05.07.2001
(iv) CVC Office Order No. 05/03/12 on F. No. 006/MSC/38 dated 26.03.2012
(v) CVC Office Order No. 05/09/14 on F. No.006/MSC/038/259085 dated 02.09.2014
(vi) CVC Office Order No. 06/08/19 on F. No. 006/MSC/038 (Part)/429692 Dated 21.08.2019
(vii) CVC Office Order No. 01/01/2020 dated 15.01.2020 on F. No. 006/MSC/038 (Part)/445413
(viii) CVC Office Order No. 14/08/21 dated 19.08.2021 on F. No. 006/MSC/038 (Part) 489810
(ix) CVC Addendum dated 10.11.2021 on F. No. 006/MSC/038/4986385 Dated 10.11.2021
(x) CVC Office Order No. 02/01/22 dated 09.01.2022 on F. No. 006/MSC/038

Central Vigilance Commission, vide its Office Order No. 02/01/22 dated 06.01.2022 had extended the scope of Advisory Board for Banking and Financial Frauds (ABBFF), to examine the role of all levels of officials/Whole Time Directors (WTDs) [including ex-officials/ex-WTDs] in Public Sector Banks, Public Sector Insurance Companies and other Public Sector Financial Institutions, in fraud cases involving amount of Rs. Three Crores and above.

....contd

2. Keeping in view the Commission's Office Order dated 06.01.2022, the Commission has directed that the Chief Vigilance Officers (CVOs) of the organizations concerned should ensure that advice of ABBFF is also obtained in respect of all cases, which are covered under the extended scope of examination by ABBFF.

3. The Commission has further directed that in respect of all eligible cases, the CVOs may ensure that recommendations/advice of ABBFF is obtained, as per SOP circulated from the Commission.

4. Further, at the time of approaching the Commission for advice in respect for any prosecution sanction case, the CVO should provide the following information also: -

(i) Whether the case was eligible for being referred to ABBFF;
(ii) If yes, the date of reference made to ABBFF be indicated;
(iii) The recommendations/advice given by ABBFF may be indicated.

5. The above directions may be noted for strict compliance, henceforth.

(Rajiv Verma)
Director

To

1. All Chief Executives of Public Sector Banks, Public Sector Insurance Companies & Public Sector Financial Institutions.

2. All CVOs of Public Sector Banks, Public Sector Insurance Companies & Public Sector Financial Institutions.

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स,
ब्लॉक–ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-I0023

सं./No. 020-VGL-054/502950

दिनांक / Dated 03.02.2022

Circular No. 07/02/22

Subject:- **Transfer/Posting of officers/officials working in Vigilance Unit of the organization- reg.**

Reference:-

(i) Commission's Circular No. 98/VGL/60	dated 15.04.1999
(ii) Commission's Circular No. 98/VGL/60	dated 02.11.2001
(iii) Commission's Circular No. 17/4/08	dated 01.05.2008
(iv) Commission's Circular No. 02/01/12	dated 04.01.2012
(v) Commission's Circular No. 03/09/13	dated 11.09.2013
(vi) Commission's Circular No. 03/04/21	dated 05.04.2021

Central Vigilance Commission, as part of its functions relating to exercising supervision over vigilance administration of the organizations under its advisory jurisdiction, has issued guidelines relating to transfer of officers/officials working in Vigilance Units of the respective organizations. Based on the inputs/requests received from various organizations and in view of DoPT's Office Memorandum No. 372/7/2016-AVD-III dated 28.04.2017 relating to appointment and tenure of Chief Vigilance Officers, the Commission has reconsidered the matter relating to posting/transfer of officers/officials working in Vigilance Units of the respective organizations.

2. The Commission has directed that initial posting of an officer/official in Vigilance Unit of an organization should be for a period of three years only. If considered necessary, the tenure of the vigilance functionary may be extended for a minimum period of three months and a maximum of two years. only after review, which shall be based on his efficiency, integrity and requirement for completion of work on hand, etc. The continuation of an officer/official in Vigilance Unit beyond three years, shall be subject to concurrence of the Chief Vigilance Officer concerned. In case, CVO's position is vacant, concurrence of the Head of Vigilance Unit shall be required for granting extension of tenure beyond three years.

3. After transfer of an officer/official from Vigilance Unit, irrespective of the period for which he has served there, he should undergo a cooling off period of at least two years, before being considered for posting in Vigilance Unit again, if necessary.

4. The Commission has further directed that an exercise may be conducted and completed latest by 31.03.2022, by the respective organizations, to identify those officers/officials, who have completed the tenure of three years/five years (as on 31.03.2022) in Vigilance Unit. In case, services of an officer/official are required beyond the period of three years, such officers/officials may be identified and the process for their retention in Vigilance Unit (for a minimum period of three months and a maximum period upto two years) should be completed by 31.03.2022. Those officers/officials, who have completed three years as on 31.03.2022 and are not being considered for further extension, should be transferred latest by 30.06.2022. Further, in respect of those officers/officials, who have completed the tenure of five years as on 31.03.2022, the exercise of their transfer and relieving out of Vigilance Unit should also be completed by 30.06.2022. A compliance report regarding retention/transfer of all such vigilance personnel, may be reported/uploaded under Para (9) of the Quarterly Performance Reports, beginning from June, 2022.

5. It may be noted that the above guidelines are to be adhered to strictly and it may be ensured that:-

(a) None of the officers/officials in Vigilance Unit is retained beyond the period of three years, without the concurrence of CVO and approval of the Competent Authority.

(b) None of the officers/officials should continue in Vigilance Unit beyond the period for which extension has been granted, after initial tenure of three years (the extended period may be for a minimum of three months and a maximum upto two years).

(c) In case of non-performance of the vigilance functionary or due to any other sensitive issue, the Competent Authority may transfer the vigilance officer/official, any time during his posting in Vigilance Unit, with concurrence of the Chief Vigilance Officer.

6. In case of disagreement between the CVO and the Competent Authority regarding retention/transfer of any officer/official, which is not finally resolved, the matter may be placed before the Chief Executive of the organization concerned for a final decision. In case, the Competent Authority is the Chief Executive of the organisation, the matter may be placed before the Board of Directors/Governing body of the organisastion or Secretary of the administrative ministry, for resolving the difference.

7. In order to ensure proper manpower strength in Vigilance Units, adequate number of suitable officers/officials should be provided. It should also be ensured that proper

replacement is provided at the time of transfer of officers/officials, so that proper manpower strength is maintained in the Vigilance Units.

8. The above instructions may be noted for strict compliance.

(Rajiv Varma)
Director

To

(i) The Secretaries of all Ministries/Departments of GoI
(ii) All Chief Executives of CPSUs/Public Sector Banks/Public Sector Insurance Companies/Autonomous Bodies etc.
(iii) All CVOs of Ministries/Departments of GoI/CPSUs/Public Sector Banks/Public Sector Insurance Companies/Autonomous Bodies etc.
(iv) Website of CVC

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स,
ब्लॉक–ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-10023

सं./No. 004/VGL/020

दिनांक / Dated 11.02.2022

Office Order No. 08/02/22

Subject:- Procedure for Handling of complaints sent for necessary action to the organisations concerned-reg.

The Central Vigilance Commission has in place a well defined Complaint Handling Policy since years. Every year on an average more than 25000 complaints are received in the Commission from various sources. The Commission has developed a dedicated portal i.e. www.portal.cvc.gov.in for lodging online complaints, subsequent to which, the system of accepting complaints through e-mails was discontinued. However, it is found that complainants are continuing sending complaints on the mail IDs of officers of the Commission also.

2. Further, there is also a defined mechanism in place where complaints received from Whistle Blowers, under the provision of Public Interest Disclosure and Protection of Informer Resolution (PIDPIR) are handled by a separate set of guidelines. Recently the same have been reviewed/updated and do not require further review of mechanism for PIDPI Complaint Handling mechanism.

3. On receipt of the complaints in the Commission through normal channel (other then PIDPI complaints), after due scrutiny at appropriate level, decision is taken for one of the following actions on the complaints:-

a) To file Anonymous/ Pseudonymous complaints.

b) To seek Factual Report from CVO of the organisation concerned, where a llegations made in the complaints are indicative of serious misconduct having vigilance angle, but adequate information is not provided by the complainant. Further action is taken after receipt of Factual Report from the CVO.

c) To send complaint to CVO for Investigation and to submit Report to the Commission. Further actions are taken after receipt of investigation report.

d) Other complaint not falling in any of the above categories are sent to CVO for necessary action and are to be dealt at their end only.

4. The Commission has been receiving communication from the complainants in respect of action taken as per para 3(d) above. The main grievance of the complainants is of not getting any response from the respective CVOs. Since, in respect of complaints sent for necessary action to the CVOs concerned, all further action are to be taken at CVOs level only, there is no mechanism available with the Commission to inform the complainant about the status of their complaints in case they approach the Commission for the same.

5. In order to assess the situation and find practical solutions to bring transparency in the process in respect of complaints sent by the Commission to CVOs for necessary action, the Commission had detailed deliberations on 10/02/2022 with officers of the Commission and CVOs of NTPC, GAIL, PNB and Ministry of Defence.

6. After detailed deliberations, it was felt that the present mechanism of handling of complaints sent for necessary action to the CVOs, has some gaps as it does not provide "end to end" solution.

7. It has therefore, been decided by the Commission to form a committee to look at each and every aspect, including usage of technology and give recommendations so that revised guidelines under Complaint Handling Policy of the Commission may be issued before 31.03.2022 relating to those complaints which are being sent to CVOs for "necessary action".

8. The Committee shall comprise of following members:-

1. Shri P. Daniel, Secretary, CVC	-	Chairperson
2. Shri Shiv Ratan Agarwal, Director, CVC	-	Member
3. Shri Rajiv Verma, Director, CVC	-	Member
4. Smt Trishaljit Sethi, CVO, NTPC	-	Member
5. Smt. Shubha Naresh Bhambhani, CVO, GAIL	-	Member
6. Shri V.K. Tyagi, CVO, PNB	-	Member
7. Shri Naveen Jain, CVO, Ministry of Defence	-	Member
8. Smt. M. Janaki,Director, CVC	-	Convenor

9. The Committee would take up the above task with immediate effect and come out with recommendations for modifications of guidelines under Complaint Handling Policy for achieving "end to end" solution in respect of complaints sent to CVOs for necessary action. The Committee would also give its recommendations about the manner in which complaints can be lodged with the Commission.

10. The Committee is expected to work on fast track basis so that revised guidelines can be finalized and issued by 31/03/2022.

11. This order is being issued with the approval of the Commission.

(Rajiv Verma)
Director

To

(i) Members of the Committee
(ii) Commission's Website

Telegraphic Address :
"SATARKTA: New Delhi

E-Mail Address
cenvigil@nic.in

Website
www.cvc.nic.in

EPABX
24600200

फैक्स / Fax : 24651186

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स,
ब्लॉक–ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-110023

सं. / No. 021-AIS-1(2)- 507570

दिनांक / Dated 16.03.2022

OFFICE MEMORANDUM

******

Subject:- Revised Proforma for furnishing details of officers by the Cadre Controlling Authorities while seeking vigilance clearance-modification of Point No. 13- reg.

*****

Kind attention is invited to the Central Vigilance Commission`s OM of even number dated 30.09.2021 vide which 13-point proforma for capturing departmental inputs on antecedence of concerned officer has been circulated. The revised proforma has two distinct parts (Part-I & II) which are to be submitted separately, under the signature of CVO/HOD. Prior to this, the departmental inputs were captured in 12-point proforma. The additional point (Point No 13) of the revised proforma captures information on complaint(s) pending against the concerned officer, along with its relevant details (i.e. age/status/gist etc).

2. The Central Vigilance Commission discharges its functions and duties, as mandated under the CVC Act, 2003, amended from time to time. Para 3.3 (a) of the comprehensive guidelines issued by the Central Vigilance Commission vide its circular No. 25/12/21 dated 24.12.2021 (F. No. 021/VGL/051) on complaint handling mechanism reads as under:

> "Central Vigilance Commission deals with complaints in the matters of corruption and irregular acts having vigilance angle."

Similarly, Para 1.4.9 of Chapter-I of Vigilance Manual (updated 2021) also stipulates that administrative misconduct would be dealt by the disciplinary authority in an appropriate manner. If lapse is without vigilance angle, the disciplinary authority would be within its rights to initiate appropriate penalty proceedings against erring employees.

3. Keeping in view the above, the Commission has decided to modify Point 13 of proforma, as under:

Present Provision

"13. Whether any complaint is pending against the officer [if so, details to be furnished]"

Revised Provision

"13. Whether any complaint **with vigilance angle** is pending against the officer [if so, details to be furnished]"

4. The 13-point proforma with above modification may be used for departmental input on antecedence of officers. A copy of the prescribed proforma, along with ibid modification, is enclosed herewith for information, and use by administrative ministries/department/ organisations.

5. This issues with approval of the Commission.

(Anirban Biswas)
Under Secretary

To.

(i) The Secretaries of all Ministries / Departments of GoI
(ii) All CVOs as per Portal (through NIC)

Copy forwarded to Sr. TD, NIC, CVC-with a request to upload it on the Commission's website and notifying CVOs through the portal.

(Anirban Biswas)
Under Secretary

PARTICULARS OF THE OFFICERS FOR WHOM VIGILANCE COMMENTS / CLEARANCE BEING SOUGHT

(To be furnished and signed by the CVO or HOD)

1. Name of the Officer (in full) :
2. Father's name :
3. Date of Birth :
4. Date of Retirement :
5. Date of Entry into Service :
6. Service to which the officer belongs including batch / year cadre-etc wherever applicable :
7. Positions held (During the ten preceding years) :

S.No.	Organization (Name in full)	Designation & Place of posting	Administrative / nodal Ministry / Deptt. Concerned (in case of officers of PSUs etc.)	From	To

DATE:

(NAME AND SIGNATURE)

VIGILANCE PROFILE OF OFFICERS FOR WHOM VIGILANCE COMMENTS / CELARANCE BEING SOUGHT

(To be furnished and signed by the CVO or HOD)

Name of the Officer :

8. Whether the officer has been placed on the "Agreed List" or "List of Officers of Doubtful Integrity". (If yes, details to be given) :

9. Whether any allegation of misconduct involving vigilance angle was examined against the officer during the last 10 years and if so with what result (*) :

10. Whether any punishment was awarded to the officer during the last 10 years and if so, the date of imposition and details of the penalty (*) :

11. Is any disciplinary / criminal proceedings or charge sheet pending against the officers, as on date. [If so, details to be furnished – including reference no.. if any, of the Commission] :

12. Is any action contemplated against the officer as on date [If so, details to be furnished (*) :

13. Whether any complaint **with vigilance angle** is pending against the officer [If so, details to be furnished]. :

DATE: (NAME AND SIGNATURE)

(*) If vigilance clearance had been obtained from the Commission in the past, the information may be provided for the period thereafter.

Telegraphic Address :
"SATARKTA: New Delhi

E-Mail Address
cenvigil@nic.in

Website
www.cvc.nic.in

EPABX
24600200

फैक्स / Fax : 24651186

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स,
ब्लॉक–ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-110023

सं. / No. No. 021-AIS-6(7)

दिनांक / Dated 16-03-2022

OFFICE MEMORANDUM

*****

Subject:- Confirmation on timely submission of Annual Immovable Property Return (AIPR) in the proposals seeking input of the Commission on vigilance status of officers for empanelment– reg.

****

Department of Personnel & Training's OM No. 11012/11/2007-Estt.A dated 27.09.2011 (copy enclosed) conveys the decision of the Govt of India that members of Central Civil Services/Posts who fail to submit Annual Immovable Property Returns of the relevant year within the prescribed time limit, would be denied vigilance clearance and they will not be considered for empanelment for senior level posts in Government of India. It has inserted sub-para 2(f) which reads as under, in the Department of Personnel & Trainings earlier OM No. 11012/11/2007-Estt.A dated 14.12.2007:

> "(f) Vigilance clearance shall be denied to an officer if he fails to submit his annual immovable property return of the previous year by 31st January of the following year, as required under Government of India decision under Rule 18 of the Central Civil Services (Conduct) Rule, 1964."

2. Similarly, as per Rule 16(2) of AIS (Conduct) Rules, 1968, officers are required to submit property return latest by 31st January of each year, and Department of Personnel & Trainings has clarified that those who fail to submit the return on time will be denied vigilance clearance.

3. It is thus, evident that filing of AIPR on time is a mandatory pre-condition for grant of vigilance clearance. So far, the Commission has not been collecting information on AIPR filing while considering proposals for vigilance clearance, and screening to this effect is left to the concerned Ministry/Department/Organization. However, some proposals received by the Commission do contain information on AIPR filing by the concerned officers, and the same is taken in account while finalising input on their vigilance status.

Contd.

4. As timely filing of AIPR is a mandatory pre-condition for vigilance clearance, all Ministries/Departments/Organizations are requested to ensure that all officers, for whom vigilance input is solicited from the Commission, have filed AIPR within the stipulated time limit. In future, confirmation on timely filing of property return by concerned officer(s), or deviation in this regard, may also be recorded on the covering letter of proposals seeking vigilance clearance from the Commission, to avoid delay in processing of the cases.

5. The above guidelines may be noted for strict compliance.

(Anirban Biswas)
Under Secretary

To,

(i) The Secretaries of all Ministries/Departments of GoI.

(ii) All CVOs as per Portal (through NIC).

Copy forwarded to Sr. TD, NIC, CVC-with a request to upload it on the Commission's website and notifying CVOs through the portal.

(Anirban Biswas)
Under Secretary

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स,
ब्लॉक–ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-10023

सं./No. 000/VGL/018/507722

दिनांक / Dated 21.03.2022

Circular No.11/03/22

Sub:- Implementation of final penalty orders issued by the Competent Authority and submission of compliance report – reg.

As per the mandate given in Section 8(1) of the CVC Act, 2003, the Central Vigilance Commission tenders advice in vigilance matters to the Organizations concerned, in respect of the officers covered under Commission's jurisdiction.

2. After completion of Departmental Proceedings, final orders are issued against the Charged Officer(CO) by the Competent Authority, imposing an appropriate penalty on him, if the charges against the CO are found to be proved. The Commission and the CVO are also informed about issuance of final orders. However, it has come to the notice of the Commission that there have been instances where even after issuance of the final orders imposing the penalty, the orders are **not** implemented in reality, thus making the whole process of disciplinary proceeding infructuous.

3. The Commission has, therefore, decided that in order to ensure end to end action, the Chief Vigilance Officers of the organisations concerned should confirm about implementation of the final Penalty Orders issued in respect of each Charged Officer, who were found guilty, against whom advice for departmental action was tendered by the Commission.

4. A compliance report in this regard, for the calendar years 2020 and 2021, should be forwarded to the Commission latest by 30.06.2022. In continuation, the Chief Vigilance Officers of respective organisations should also submit an Annual Compliance Report about implementation of final Penalty Orders in respect of each such charged officer, latest by 30th June of every year, for the previous calendar year.

Contd....2...

5. A draft format of the report/statement (to be duly signed by the CVO concerned) is also enclosed as Annexure I.

6. It may be noted for strict compliance in future.

(Rajiv Verma)
Director

To

(i) All Secretaries of Ministries/Departments of GOI
(ii) All Chief Executives of CPSUs/Public Sector Banks/Public Sector Insurance Companies/Autonomous Bodies etc.
(iii) All CVOs
(iv) Website of CVC

Annexure-I

Name of Organisation: _____

Period: _____

This is to certify that penalty imposed on the Charged Officers during the aforementioned period, on the basis of advice tendered by the Central Vigilance Commission, has been implemented by the authorities concerned.

Signature and Name of CVO.

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
ब्लॉक–ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-10023

सं./No. 022/VGL/032
दिनांक / Dated... 11.07.2022

Circular No. 14/07/22

Subject: Updation of Manual on Procurement of Goods, Services, Works and Consultancy, etc.

Central Vigilance Commission and D/o Expenditure have issued guidelines on public procurement from time to time.

2. After due deliberations, it was decided that for the sake of uniformity and to avoid multiplicity of authorities for issuance of guidelines on procurement related issues, updated Manuals may be issued by D/o Expenditure only, after taking into consideration the guidelines issued by the Commission. Accordingly, D/o Expenditure have updated and released *i) Manual on Procurement of Goods; ii) Manual on Procurement of Works; and iii) Manual on Procurement of Consultancy & Other Services, wherein the guidelines issued by the Commission on public procurement has also been assimilated.* The same are available on Commission's website i.e. www.cvc.gov.in under the head "Guidelines" and sub-head "Tender Guidelines".

3. The Commission has desired that all the Chief Vigilance Officers may take note of the updated Manuals and bring the same to the notice of Chief Executive/Management of their organisation, along with other authorities concerned, for strict compliance henceforth. An introductory note relating to updated Manuals, as quoted above, is enclosed for guidance and reference purpose.

(Rajiv Verma)
Director

Encl: As above

Central Vigilance Commission
सत्यमेव जयते
New Delhi

To,

(i) The Secretaries of all Ministries/Departments of GoI
(ii) All Chief Executives of CPSUs/Public Sector Banks/Public Sector Insurance Companies/ Public Sector Financial Institutes/ Autonomous Bodies etc.
(iii) All CVOs of Ministries/Departments of GoI/CPSUs/Public Sector Banks/Public Sector Insurance Companies/Public Sector Financial Institutes/Autonomous Bodies etc.
(iv) Website of CVC

Central Vigilance Commission

Central Vigilance Commission (CVC) has been issuing various guidelines on Public Procurement from time to time. So far, in all 72 number of circulars containing issue specific guidelines were issued and were also hosted on Commission's website.

2. Apart from the guidelines issued by CVC, Department of Expenditure (DoE), Government of India has also been issuing guidelines on public procurement including manuals on procurement of goods, works and consultancy & other services.

3. On other occasions, various other Organisations like NITI Aayog, D/o Promotion of Industry & Internal Trade have also issued guidelines on public procurement. CVC after deliberations with DoE and within the Organisations has come to logical conclusion that it would only be appropriate if public procurement guidelines are issued from D/o Expenditure. Due to multiple organizations issuing guidelines, procurement executives were facing problems in having a single authoritative source of reference.

4. DoE in collaboration with CVC has now updated (i) Manual on Procurement of Goods, (ii) Manual on Procurement of Works (iii) Manual on Procurement of Consultancy & Other Services, wherein all the CVC guidelines on public procurement have been merged.

5. These updated Manuals have been released by Cabinet Secretary in the office of Central Vigilance Commission on 1st July, 2022 in presence of CVC and Finance Secretary. Secretaries of various Ministries/Departments, Heads of PSUs/PSBs, officials of CVC, officials of DoE etc. were also present.

6. These updated Manuals of D/o Expenditure have been uploaded on the website of CVC and all the earlier guidelines of CVC on public procurement have been withdrawn. All the Organisations are required to update/align their procurement guidelines/manuals in line with the above Manuals of D/o Expenditure and upload them on their website at the earliest for easy access of their officials and other stakeholders.

******

Central Vigilance Commission
सत्यमेव जयते

Telegraphic Address :
"SATARKTA: New Delhi

E-Mail Address
cenvigil@nic.in

Website
www.cvc.nic.in

EPABX
011-24600200

फैक्स / Fax :
011-24651186

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स,
ब्लॉक–ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-110023

सं./No. 022/VGL/041-520101

दिनांक / Dated 29.07.2022

Circular No. 15/07/22

Sub:- Intimation to CVC & CBI in cases pending for sanction for prosecution – reg.

The Central Vigilance Commission, as the apex integrity institution, is mandated to fight corruption and to ensure integrity in administration. Section 8(1)(f) of CVC Act, 2003, mandates the Central Vigilance Commission to review the progress of the applications pending with the Competent Authorities for sanction of prosecution under the PC Act, 1988.

2. In terms of the directions of the Hon'ble Supreme Court in the case of Shri Vineet Narain, guidelines prescribed by the Department of Personnel & Training and the Commission, as well as the amendments made to Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988, the competent authorities are required to take a decision on the requests for grant of sanction for prosecution within a period of three months. In respect of cases where any legal consultation is required, such period may, for reasons to be recorded in writing, be extended by a further period of one month.

3. It has been noticed that after the advice of the Commission, the Competent Authority concerned sometimes send the matter either to their Administrative Ministry or DoPT for final decision, without intimation to CVC or CBI. In order to keep the CVC and CBI informed of the stage in which the case is pending, all the Competent Authorities are required to mark a copy to CVC and CBI of their communications with DoPT/CVC/CBI/ Administrative Ministry on such cases.

4. All the Chief Vigilance Officers may bring this to the notice of the competent authorities concerned of their respective organisations accordingly.

(Vivek Kumar)
Director

(i) Secretary, D/o Personnel & Training
(ii) Director, CBI
(iii) All the Chief Vigilance Officers of Ministries/Department of GoI/CPSEs/PSBs/ PSICs/ FIs and Autonomous Bodies etc.
(iv) Website of CVC

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स,
ब्लॉक-ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-10023

सं. / No..................021/MSC/022/
522528

दिनांक / Dated......29.08.2022....

Circular No. 17/08/22

Subject: Uploading of Commission's Circulars/Guidelines, subsequent to release of Vigilance Manual-2021 – Reg.

Central Vigilance Commission brought out updated Vigilance Manual – 2021, comprising of all the instructions, guidelines, circulars, etc. relating to various aspects of Vigilance Administration, as issued from time to time.

2. Subsequent to the release of Vigilance Manual – 2021, the Commission has issued certain guidelines/circulars, as and when required, covering different aspects of Vigilance Administration. In order to facilitate easy access and reference to these guidelines, the same have been uploaded on the Commission's website i.e. www.cvc.gov.in under the head "Manuals" and sub-head 'Vigilance Manual – Amendments' so that all the guidelines/circulars (Issued subsequent to release of Vigilance Manual – 2021) are available at a common place. The link for the "Vigilance Manual – Amendments" is https://cvc.gov.in/?q=guidelines/vigilance-manual. All subsequent guidelines to be issued in future would also be available on Commission's website, under the sub-head 'Vigilance Manual – Amendments'.

3. All concerned are requested to take note of the same for use/reference, as and when required.

(Rajiv Verma)
Director

To,

(i) The Secretaries of all Ministries/Departments of GoI
(ii) All Chief Executives of CPSUs/Public Sector Banks/Public Sector Insurance Companies/ Public Sector Financial Institutes/ Autonomous Bodies etc.
(iii) All CVOs of Ministries/Departments of GoI/CPSUs/Public Sector Banks/Public Sector Insurance Companies/Public Sector Financial Institutes/Autonomous Bodies etc.
(iv) Website of CVC

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स,
ब्लॉक–ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-10023

सं./No. 022/VGL/045

दिनांक / Dated 01.09.2022

Circular No. 18/09/22

Subject: Clarification regarding the enquiry/investigation to be conducted against officers on deputation.

Central Vigilance Commission, vide Para 5.6 of Chapter-V of Vigilance Manual – 2021 has prescribed the procedure for handling complaints/allegations against officers on deputation to other organizations.

2. As per procedure laid down in Para 5.6, in case of allegation of misconduct in the borrowing organisation, against an officer who was on deputation to that organisation and has since repatriated to his parent organisation, the same is to be enquired into by the CVO of the borrowing organisation.

3. However, it has come to the notice of the Commission that some organisations are under the impression that in case the borrowed officer has gone back to his parent organisation, then the allegation of misconduct is to be forwarded to the parent organisation for enquiry by the CVO of the parent organisation.

4. It is clarified that in case of receipt of any complaint/allegation of misconduct against an officer borrowed from another organisation (and since repatriated to the parent organisation), the same should be enquired into by the CVO of the borrowing organisation and after the enquiry, the facts should be brought to the notice of the parent organisation.

5. In order to bring clarity, the part of Para 5.6 "If a misconduct is detected in the borrowing Department/Organization on the part of an officer after his repatriation to his parent Department/Organization, the then borrowing Department/Organization should bring the fact of the matter to the notice of the parent Department/Organization which will decide the further course of action" stands modified to the above extent and may be read as under:

"If a misconduct is detected in the borrowing Department/Organization on the part of an officer after his repatriation to his parent Department/Organization, then ***the*** borrowing Department/Organization should bring the fact of the matter, ***after due enquiry by the CVO,*** to the notice of the parent Department/Organization which will decide the further course of action".

6. Other part of Para 5.6 of Chapter-V of Vigilance Manual - 2021 remains unchanged.

It may be noted for future compliance.

(Rajiv Verma)
Director

To

(i) The Secretaries of all Ministries/Departments of GoI
(ii) All Chief Executives of CPSUs/Public Sector Banks/Public Sector Insurance Companies/ Public Sector Financial Institutes/ Autonomous Bodies etc.
(iii) All CVOs of Ministries/Departments of GoI/CPSUs/Public Sector Banks/Public Sector Insurance Companies/Public Sector Financial Institutes/Autonomous Bodies etc.
(iv) Website of CVC.

सतर्कता जागरूकता सप्ताह
VIGILANCE AWARENESS WEEK

31st October - 06th November, 2022

''भ्रष्टाचार मुक्त भारत-विकसित भारत''

"Corruption free India for a developed Nation"

सतर्कता विभाग, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
Vigilance Department,THDC India Limited

PART-II

SYSTEMIC IMPROVEMENTS SUGGESTED BY VIGILANCE DEPARTMENT

Sub.: Systemic Improvement with regard to preparation and checking of the Estimates

During an intensive examination of a work by Vigilance department, it is observed that -

(i) Approved drawings with dimensions were not made part of the estimate. Cost Engineering department, during technical vetting, mentioned in the checking note that the quantities taken by the execution department have been assumed to be correct. Vigilance department is of the view that Cost Engineering department should have checked the quantities from drawings for Technical vetting.

(ii) Bidder has quoted abnormally low rates for certain items which were accepted without ensuring the minimum wages.

(iii) Execution department has considered the older edition of DSR/DAR for analysis of rates, whereas the new edition had been published.

Observations & Suggestions:

(i) As per THDC Work Manual - 2012, Appendix- Guidelines on pre-award activities, "For the purpose of Technical vetting of work proposal by the Technical Cell, detailed technical drawing duly approved by HOD should be furnished". Approved drawings should be made part of the proposal essentially.

(ii) To ensure minimum wages payment for such type of works, an office order No.THDC/RKSH/CC/P&A-GH/2652 dtd. 12.07.2019 was issued by GM(Corp. Contracts) which was subsequently made part of the DOP on 18.09.2019. This Order is to be followed in true spirit.

(iii) Technical cell/Finance Deptt. is required to check the estimate following appropriate DSR/CPWD rates etc. as per THDC Works Manual.

विषय: अचल संपत्ति विवरण के संबंध में (प्रणालीगत सुधारात्मक परिपत्र)

टीएचडीसी के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वार्षिक अचल सम्पति का विवरण HRMS पोर्टल पर ऑनलाइन भरकर जमा किया जाता है। DPE द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में सतर्कता विभाग द्वारा कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के अचल संपत्ति विवरण की क्रम रहित (Random) आधार पर संपत्ति की सीमित संवीक्षा की गई थी। पूर्व में भी संवीक्षा के दौरान अचल सम्पति विवरण में अपूर्ण सूचना/जानकारी पाये जाने पर सतर्कता विभाग द्वारा एक प्रणालीगत सुधारात्मक परिपत्र (टीएचडीसी/ऋषि/सतर्कता/F-82/1265-82, दिनांक 20.09.2019 को जारी किया गया था । किन्तु अभी भी यह पाया गया है कि कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अचल सम्पति विवरण के विभिन्न कॉलमों के अनुसार सही/पूर्ण जानकारी नहीं भरी जा रही है। अचल संपत्ति विवरण- 2020 की संवीक्षा में कुछ निम्न मुख्य बिन्दु पुनः संज्ञान में आये है:

1. यह पाया गया है कि कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अचल संपत्ति विवरण में अंकित विभिन्न कालमो जैसे सम्पति विवरण के Precise Location (Name of district, Division, Taluk and village in which property is situated and also its distinctive No.) के अंतर्गत संपत्ति से सम्बंधित मांगी गयी जानकारी या तो भरी नहीं जाती है अथवा अधूरी भरी जाती है।
2. Nature of land के अंतर्गत कॉलम में संपत्तियों से सम्बंधित जानकारी सही/पूर्ण नहीं भरी जाती है।
3. Extent of Interest के अंतर्गत कॉलम में संपत्तियों के Extent of Interest को % के अनुसार नहीं भरा जाता है।
4. How acquired के कॉलम में संपत्ति से सम्बंधित जानकारी नही भरी जाती है।
5. Name with detail of person/Agency from whom acquired कॉलम के अंतर्गत संपत्ति किससे खरीदी गयी है, उसका पता/विवरण की जानकारी नहीं दी जाती है या अधूरी होती है।
6. Cost of Acquisition कॉलम के अंतर्गत धनराशि को कॉलम में दी गई यूनिट (लाख में) के अनुसार सही नहीं भरी जाती है अथवा खाली छोड़ दी जाती है।
7. Self-saving/Loan from THDC /Loan from Bank /FIs/Loan from Relatives/Other sources कॉलम के अंतर्गत संपत्तियों से सम्बंधित पूर्ण जानकारी/धनराशि को कॉलम में दी गई पूनिट (लाख में) के अनुसार सही नहीं भरी जाती है अथवा खाली छोड़ दी जाती है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि संपत्तियों के क्रय हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था किस प्रकार से की गयी है।
8. Present value of the property कॉलम के अंतर्गत संपत्तियों से सम्बंधित जानकारी/धनराशि को कॉलम में दी गई यूनिट (लाख में) के अनुसार भरा जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए यदि सम्पति की कीमत रू 20,50,000/- है तथा कॉलम की यूनिट लाख (in lakh) में है तो कॉलम के अंतर्गत सूचना 20.50 ही दर्शाई जानी चाहिए।

अचल संपत्ति विवरण की सीमित संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा संपत्ति के खरीद अथवा बेचे जाने की दशा में सक्षम अधिकारी को पूर्व सूचना/अनुमति नहीं ली गई है। यहाँ यह भी अवगत करना आवश्यक है कि टीएचडीसी CDA Rule-19 के अंतर्गत अचल संपत्ति की खरीद अथवा बेचे जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी को समय से सूचना देने / अनुमति ली जानी आवश्यक है।

सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वर्ष-**2021** की अचल संपत्ति विवरण को माह जनवरी-**2022** में भरा जाना है जिसके लिए **HR**-स्थापना विभाग से सभी को दिशा निर्देश जारी किये जाने अपेक्षित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करने कष्ट करें कि उनके द्वारा भविष्य में उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाय। यदि भविष्य में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया तो यह माना जायेगा कि उनके द्वारा जानबूझ कर सूचना/ जानकारी को छुपाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध टीएचडीसी के प्रचलित नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

Sub.: Systemic Improvement with regard to Purchase through committee.

Vigilance Department is regularly conducting Intensive Examination and Surprise inspections of Works/ Purchase Orders etc. at Projects as well as other offices of THDCIL. During investigation following short comings were observed in one of the Purchase Case:

(iv) Quotations received from the firms were signed by the Committee Members without date.

(v) Comparative Statement was signed by the Committee Members without any date.

(vi) Subsequent to receipt of material by the Indenter, Stock Register page number was indicated on the Invoice but without any signature.

(vii) Bill was not verified before sending it to Finance Deptt. for payment.

(viii) Following certificate in compliance of clause no. 4.3.2(d) of THDC Procurement Policy-2009 was not given by the purchase committee:

"Certified that we ..... members of the purchase committee are satisfied that the goods purchased / recommended for purchase are of the requisite specification and quality, priced at reasonable rate and the supplier recommended is reliable and competent to supply the goods in question".

In view of above, it is requested that all HOPs / HODs at Project, Corporate Office and other locations may please direct all the officers / employees to take a note of above observations of vigilance department while processing the purchase cases through committee to ensure strict compliance of THDCIL's Procedures and Policies.

Sub: Systemic Improvement with regard to %age Checking/Verification of measurements in MB by executives of Execution Deptt.-Regarding.

The Vigilance department is regularly conducting Intensive examinations/ Surprise inspections of works at project sites as well as other offices of THDCIL as a part of Preventive Vigilance. During scrutiny of some project works, it has been observed that the executives of the execution deptt. have not checked/ verified the measurements as per the requirement circulated by Company Secretary vide Office Order-01/2018 dtd. 27.02.2018: "Amendment in Clause No. 4.3.2 of THDC Works Manual-2012".

The recorded measurements for work done in MB is the basis of payment against the Contract Agreement, therefore, checking/verification of the measurements by the appropriate level officers as per the guidelines issued is the prime responsibility of the concerned officers and cannot be compromised.

In view of above, it is requested that all concerned departments be directed to take a note of the observations of the vigilance deptt. and to ensure strict compliance of the above office order dtd. 27.02.2018 issued with regard to minimum % age checking of the measurements.

Subject: Standard guidelines for contractor profit/Overheads considered in manpower engagement works and its applicability on EPF, ESI, hidden charges etc.

With a view to develop Uniform and Standard Criteria with regard to contractor profit/Overhead considered in manpower engagement works and its applicability on EPF, ESI hidden charges etc, the following system shall be adopted while preparing and processing the estimates in all future contracts by all concerned offices/projects/ units of THDCIL.;

1. Manpower engaged directly in supply/ Annual maintenance/R&M contract of Guesthouse/ Canteen, Horticulture, Electrical, water supply etc.;

   The cases where manpower is directly engaged as outsourcing/Annual maintenance/R&M of Guest house/canteen, Horticulture, Electrification, water supply etc., following shall be considered while preparing estimates related to engagement of manpower.;

I. Minimum Wages as per Ministry of Labour & Employment (MOL &E), Govt of India.;
II. Employer share of EPF @ 13%, ESI @ 3.25% on minimum wages. The same shall be reimbursed on the basis of documentary proof.
III. On account of small T&P and sundries, a provision of 1.00% of minimum wages may be made, wherever applicable.
IV. Contractor profit (including overhead) @ 10% on minimum wages.
V. In case of manpower is engaged for Guest house/ Canteen, where the specific uniform is to be wear by the manpower, the same may be considered as a separate BOQ item for the provisions stated in sl. no. 4.0 of office order no. THDC/RKSH/CC/P&A-GH/2652 dtd. 12.07.2019. The estimate may be worked out as Lump sum 2% of manpower cost (Minimum wages plus Contractor profit).

2. Manpower engaged for R/M of Dam/Spillway/Power House & other associated structures, HM & EM Works within defined Project area under O&M stage.;

The cases where manpower is directly engaged as supply contract/outsourcing/ AMC for R/M of Dam/Spillway/Power House & other associated structures, HM & EM Works within defined Project area under O&M stage, following is proposed to be considered while preparing estimates related to engagement of manpower;

I. Minimum Wages as per Ministry of Labour & Employment (MOL&E), Govt of India.
II. Employer share of EPF @ 13%, ESI 3.25% on minimum wages. The same shall be reimbursed on the basis of documentary proof.
III. Hidden Charges shall be extra on the minimum wages, excluding EPF & Medical (if ESI is applicable for the location of Project) @ from 8.22 % to 14.72% on minimum wages towards, Leaves, Accommodation, Workman compensation, PPE & transportation etc. and Tunnel allowance, if applicable in line with IOM no THDCIL/Planning/P-3/136 dated 07.09.2016.
IV. Contractor profit (including overhead) @ 10% on minimum wages, Hidden charges and Tunnel allowance, wherever applicable.

The Labour Cess (if applicable) @ 1% and GST shall be extra as per actual in both the cases.

This shall come into force with immediate effect.

Sub.: Systemic Improvement with regard to Proprietary Article Certificate (PAC)

Vigilance department regularly conduct inspections of the works/Procurement etc. at Project sites as well as in other offices of THDCIL as part of preventive vigilance. During an examination of a procurement case, it has been observed that the 'Proprietary Article Certificate (PAC)' submitted by indenting department was not as per the format prescribed in 'Policies and Procedures for Procurement of Goods' Clause 4.7.3(e). No proper justification was given to procure a particular make.

As per 'Policies and Procedures for Procurement of Goods' Clause 4.7.3(e), items which are to be supplied by the manufacturer who possess 'Patent Right" of item and no equivalent or near equivalent is available from any other source, are procured as Proprietary Items. Many times,indenting department furnish the requisition for such items for which a 'Proprietary Article Certificate' is to be submitted by indenting department with the indent.

In view of above, it is requested that all concerned departments be directed to take a note of the observation of the Vigilance department, while processing the case of PAC based procurement

सतर्कता जागरूकता सप्ताह
VIGILANCE AWARENESS WEEK

31st October - 06th November, 2022

''भ्रष्टाचार मुक्त भारत-विकसित भारत''

"Corruption free India for a developed Nation"

सतर्कता विभाग, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
Vigilance Department,THDC India Limited

PART-III

लेख/ कविताएँ

Corruption Free India for a Developed Nation

Corruption prevails in every sector and at every level in the country. Corruption is a complex social, political and economic phenomenon that affects countries to its Foundations. As per United Nations, Corruption undermines democratic institutions, slows economic development and contributes to governmental instability. Corruption attacks the foundation of democratic institutions by distorting electoral processes, perverting the rule of law and creating bureaucratic quagmires whose only reason for existing is the soliciting of bribes thereby hampering the growth and development of the country.

While individual efforts can work in the direction of freeing the country from corruption however if the problem is to be removed from its roots, then government's intervention is necessary. In this regard, Indian government has made several strict laws and mechanisms to tackle corruption. Few of the many initiatives taken by the Government are introduction of Implementation of E-tendering in public procurements to ensure fair play field and competitive based bidding. Introduction of e-Governance and simplification of procedure and systems to ensure transparency and end the "Inspector Raj", Introduction of Government procurement through the Government e-Marketplace (GeM) to mandate public entities for all the procurements through GeM portal only. Discontinuation of interviews in recruitment of Group 'B' (Non-Gazetted) and Group 'C' posts in Government of India etc.

As a public entity, THDC India Limited is also committed to eradicate corruption in any form and at any level. THDC India Limited has complied with all the directions issued by the govt. from time to time to ensure transparency at workplace. Interventions like procurement through E-Tendering, GeM portal has been implemented to ensure transparency in transaction of work. THDC India Limited has framed policy such as Work Manuals, procurement policy, recruitment rules etc. which strictly adhere with the directions issued by Govt. of India from time to time. Moreover, THDC India Limited has its own Vigilance Deptt. Working under the aegis of Chief Vigilance Officer appointed by Govt. of India to keep a check on the routine transaction of work at the corporation level and issue advisory wherever needed.

THDC India limited, in order to promote Integrity and Transparency in the organization has always ensured proper measures including the areas of Procurement of Goods and Services, recruitments etc. But rules and regulations are not enough to tackle corruption and eradicate its roots until we as a responsible citizen of this country abide by these rules and committed to fight corruption.

Veer Singh
CGM-HR

क्या फ़र्क पड़ता है!

क्या फ़र्क पड़ता है, होने दो जो होता है।

किसी को नींद से क्यों जगाना,
क्या सही, क्या ग़लत, ये क्यों बताना।
सोने दो जो सोता है, होने दो जो होता है।

कर्मों का हिसाब, किसी को क्यों समझाना,
जो जड़े गहरा गई, उन्हें क्यों निकलवाना।
बोने दो जो बोता है, होने दो जो होता है।

ग़लत को सही करने की किसे पड़ी है,
कोई दुखी है, यह बात कहां बड़ी है।
रोने दो जो रोता है, होने दो जो होता है।

किसी का हक छिन जाए ग़र यहां अभी,
किसी को कहां मिलता है, सब कुछ कभी।
खोनें दो जो खोता है, होने दो जो होता है।

क्या फ़र्क पड़ता है, होने दो जो होता है।

भावना रावत
प्रबंधक (नियोजन)
टीएचडीसी आई. एल., टिहरी।

भ्रष्ट्राचार मुक्त भारत हेतु प्रयास-विकसित भारत-एक परिणाम

भारत की आजादी की ७५ वीं वर्षगाठ तक पहुँचने में धीरे धीरे ही सही, पर पूरे ७५ वर्ष का समय ही बीता है, इस कालखंड में समय नें स्वयं के प्रवाह हेतु किसी भी प्रकार का कोई लघुपथ (Shortcut) नही अपनाया है क्योंकि ब्रहमांड की उत्पत्ति में स्थान (Space) एवं समय (Time) का प्रवाह प्रकृति के अस्तित्वगत सिद्धांतों के अधीन है परन्तु इस ब्रहमांड में रहनें वाले सामाजिक प्राणी मनुष्य की आवश्यकताएं एवं इच्छाएं तथा उनकी प्राप्ति हेतु, उसके निर्माण, जीने के ढंग, लक्ष्य प्राप्ति और उसे शीघ्रता से प्राप्त करने की इच्छा मनुष्य को किसी भी प्रकार के लघुमार्ग (Shortcut) को अपनाने की ओर अग्रसर करती है और किसी भी प्रकार से समयपूर्व लक्ष्य प्राप्ति की अधीरता मनुष्य को अनुचित साधन एवं माध्यम की और धकेलती है | इसलिए हमें इस सच को इस अहसास के साथ अनिवार्य रूप से स्वीकार करना ही होगा कि प्रत्येक लक्ष्य की पूर्ति एक निश्चित समय की सीमा में ही हो सकती है, जैसे संस्कृत का निम्नलिखित श्लोक हमें इसकी प्रेरणा प्रदान करता है कि:

शनैः पन्थाः शनैः कन्था शनैः पर्वतलङ्घनम्।
शनैर्विद्या शनैर्वित्तं पञ्चैतनि शनैः शनैः ॥

"अर्थात: राह धीरे धीरे कटती है, कपड़ा धीरे धीरे बुनता है, पर्वत धीरे धीरे चढा जाता है, विद्या और धन भी धीरे-धीरे प्राप्त होते हैं, ये पाँचों धीरे धीरे ही होते हैं।" इसी प्रकार व्यक्ति/समाज/प्रदेश/देश के सर्वांगीण एवं सर्वसमावेशी विकास हेतु किये जाने वाले कर्तव्य के मार्ग का अनुगमन भले ही धीरे-धीरे ही होता है किन्तु इस दिशा में बढ़ाया गया कदम एक स्थिरता एवं स्थायित्व प्रदान करता है जो विकास के लिए एक मज़बूत आधार बनता है और मज़बूत आधार पर बने भवन/ढांचें/व्यवस्था/देश आदि में रहने वाले निवासी/नागरिकों में एक सुखद अहसास, सुरक्षा एवं विश्वास का भाव बनाये रखता है |

किसी संत का कथन है कि हर चलना कहीं पहुँचना नही होता, यदि इस कथन पर ध्यान दिया जाय तो यह महसूस होगा कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ पाना चाहता है और कहीं न कहीं किसी निर्धारित किये गए लक्ष्य तक शीघ्रताशीघ्र पहुंचना चाहता है किन्तु इस हेतु अनैतिक,अमर्यादित तथा भ्रष्ट आचरण युक्त प्रयासों द्वारा अपनाया गया छिद्रयुक्त लघुपथ (Shortcut) मार्ग किस प्रकार से लक्ष्यप्राप्ति एवं सर्वांगीण विकास में बाधक बन जाता है जिसकी बानगी संस्कृत के निम्न श्लोक में झलकती है :

सुसूक्ष्मेणापि रंध्रेण प्रविश्याभ्यंतरं रिपुः
नाशयेत् च शनैः पश्चात् प्लवं सलिलपूरवत्

"अर्थात : नाव में पानी पतले छेद से भीतर आने लगता है और भर कर उसे डूबा देता है, उसीतरह शत्रु को घुसने का छोटा रास्ता या कोई भेद मिल जाए तो उसी से भीतर आ कर वह कबाड़ कर ही देता है।"

इसी प्रकार किसी समाज, प्रदेश, देश आदि के विकास में भ्रष्टाचार का छिद्र जब बड़ा आकार लेने लगता है तो वह उस देश के विकास की राह में अवरोध उत्पन्न करके उसके विकास की धार कुंद कर देता है जिसके परिणामस्वरूप व्यवस्था में यकीन रखने वालें ईमानदार व्यक्तियों का विश्वास डोलने लगता है और उनमें एक प्रकार की निराशा एवं कुंठा का जन्म होता है | जिसके शमन के लिए प्रत्येक नागरिक से शनैः शनैः एवं धैर्यपूर्वक समाज/देश की प्रगति/विकास के लिए उनके गिलहरी जैसे योगदान की अपेक्षा रहती है |

आज़ादी के इन ७५ वर्षों में भ्रष्ट्राचार रूपी दंश के बावजूद विकसित भारत बनने की दिशा में भारतवर्ष नें ज़हां भ्रष्ट्राचार के उन्मूलन हेतु शासकीय स्तर पर सरकारी संस्थानों/विभागों के विविध लोकप्रचलित सार्थक प्रयासों, यथा: सूचना के अधिकार, नागरिक सेवाओं का ऑनलाइन पोर्टल पर एक निर्धारित समयसीमा में समाधान, GeM/E-Procurement पद्धति से सार्वज़निक खरीद प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एक राष्ट-एक राशन कार्ड, नकद लेन-देन को हतोत्साहित करना एवं डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू करवाना, विभिन्न सरकारी लाभार्थी योजनाओं के पात्र नागरिकों के खाते में सीधा भुगतान, तथा अनेकों योजनाओं में फर्जीवाड़े के रोकथाम हेतु आधार कार्ड से जोड़े जाने की व्यवस्था एवं आयकर से सम्बंधित प्रकरणों के Faceless समाधान आदि अनेकों सेवाओं के समाधान हेतु किये गए प्रयास, ज़हां भ्रष्ट्राचार को रोकनें में सहायक सिद्ध हुए हैं वहीँ दूसरी ओर विकास के मार्ग पर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाये गए विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी कदम, भ्रष्ट्राचार मुक्त भारत-विकसित भारत के सपनें को साकार करने में सफल होते दिख रहे हैं।

जी एस चौहान
वरिष्ठ प्रबंधक (सतर्कता)
ऋषिकेश

ईमानदारी

क्या लेकर आये थे, और क्या लेकर जाओगे
जो है किया यहाँ एकत्रित, सब यहीं लुटाओगे
ये धन, संपति, ऐशवर्य, वैभव, आराम
मानों सच नहीं आयेंगे कभी ये काम |

अंत उसी का होगा शानदार
रहा जो जीवन पर्यंत ईमानदार
बचपन से लिखते रहे ईमानदारी पर लेख
बडे होने पर आश्चर्य हुआ ये सच्चाई देख
कि सब ढूँढते हैं दूसरों में ईमानदारी
पर नहीं दिखाते उसमें अपनी भागीदारी |

ईमान पर बातों और भाषणों में कमी नहीं
सब खोजते हैं औरों में पर खुद रखते नहीं
क्या सिर्फ शास्त्री, कलाम तक ही सिमटा रह जायेगा
या हर पीढ़ी, नागरिक इसे आगे बढ़ाएगा |

कुछ चंद हैं जिनकी ईमानदारी नहीं बिकी
इन्ही के दम से संभली है और दुनिया टिकी
विलुप्ति के कगार पर पहुंचा, कही कहीं ही अब दिखता
बेईमानी का अंत दुखद पर गलतियों से भी कोई न सीखता |

टूटते हुए मूल्य, डूबते संस्कार के बीच यह कविता गाता हूँ
ईमानदारी की विलुप्त होती अवमूल्यन की गाथा सबको सुनाता हूँ
ईमानदारी है देवगुण, कम लोगों ने पाई है
देती बेफिक्री, इज्ज़त और शांति जिन्होने इसे कमाई है
सतर्कता दिवस देती है मौका और हमने यह ठानी है
बेईमानी के नाम से अच्छा ईमानदारी की गुमनामी है।

आशुतोष कुमार आनंद
वरिष्ठ प्रबंधक (मानव संसाधन)
एनसीआर कार्यालय, कौशाम्बी

भारत में भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी : एक पुनरावलोकन

भारतवर्ष विभिन्न स्व-शासित राज्यों/ निकायों के साथसाथ केन्द्रीय शासन का एक संघीय प्रारूप है | रक्षा, शिक्षा, नागरिक उड्डयन, रेलवे, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों के अलावा भी कई स्तरों पर सरकारी या सरकार नियंत्रित उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं | भारत में व्यापार करने के लिए सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर संपर्क आवश्यक हो जाता है | साथ ही राज्य के विभिन्न क़ानून जो कि व्यापार को प्रभावित करते हैं, सरकारी अधिकारियों को विवेकाधीन अधिकार प्रदान करते हैं| व्यापार प्रारम्भ करने और चलाने के लिए आवश्यक स्वीकृतियां, अधिनियमों का अनुपालन, रिपोर्ट्स जमा करना, निरीक्षण आदि गतिविधियाँ केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के, या इन सभी के अधिकारियों /कर्मचारियों के अधिकारों के दायरे में आती हैं, जो अपने अधिकारों और व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग भ्रष्ट गतिविधियों के लिए करते हैं |

भारत में कठोर भ्रष्टाचार निरोधी क़ानून हैं, किन्तु फिर भी यह माना जाता है, विशेषकर भारत वर्ष के बाहर, कि भ्रष्टाचार, भारतवर्ष में व्यवहारिक रूप से एक स्वीकार्य प्रक्रिया है | हालांकि भ्रष्टाचार भारत में सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से स्वीकार योग्य नहीं है | वास्तव में, विगत कुछ समय से चल रहे राजनीतिक और सामाजिक रुझान के कारण भारतीयों में भ्रष्टाचार के विरूद्ध जागरूकता एवं भ्रष्टाचार विरोधी वातावरण विकसित हुआ है, इन सब के कारण भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई अतिरिक्त तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे कि स्वतंत्र लोकपाल/लोकायुक्तों की नियुक्ति, रिश्वत देने वाले और बिचौलियों के लिए कानूनी प्रावधान को मजबूती देना, बेनामी लेन देन, अघोषित संपत्ति एवं मनीलौंड्रीगं(धनशोधन) के लिए वर्तमान कानूनों का दायरा और अधिक बढ़ाना | न्यायालयों की अतिरिक्त सक्रियता भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सहायक हैं |

रिश्वतखोरी के विरुद्ध कानूनी प्रावधान :

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988)भारतवर्ष में एक मुख्य भ्रष्टाचार निरोधी विधान है, जो सरकारी कर्मचारी को अवांछित लाभ लेने या देने को अपराधी बनाता है | कोई भी व्यक्ति या कंपनी इस एक्ट के तहत अपराध साबित होने पर दंड के दायरे में आते हैं | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी (लोक सेवक) को उसको देय वैधानिक भुगतान/ पारिश्रमिक के अलावा किसी सरकार या संगठन द्वारा, जिसमें वह कर्मचारी सेवा दे चुका हो, कोई अनुतोष/पारितोषिक/धन अवांछित लाभ की श्रेणी में आता है | किसी भी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, निगम, सरकारी कम्पनी या कोई भी संस्था जो राज्य से सहायता प्राप्त है या नियंत्रित है, में सेवा दे रहा व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में आता है | लोक सेवक द्वारा रिश्वत लेना या कोई अन्य अवांछित लाभ प्राप्त करना, आय से अधिक संपत्ति रखना या आपराधिक कदाचार आदि कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के दायरे में आते हैं | साथ ही, रिश्वत लेने के लिए उकसाने या रिश्वत देने के लिए किसी गैर सरकारी व्यक्ति या संस्था पर भी अभियोग चलाया जा सकता है | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न अपराधों के लिए ६ माह से १० वर्ष तक की सजा दी जा सकती है तथा जुर्माना भी लगाया जा सकता है | भ्रष्टाचार के द्वारा कमाई गयी संपत्ति को सरकार द्वारा जब्त किये जाने के भी प्रावधान हैं |

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अतिरिक्त भ्रष्टाचार निवारण के लिए विभिन्न निकाय, अधिनियम एवं कानूनी प्रावधान मौजूद हैं जिनमें से मुख्य निम्न प्रकार हैं _

1. Indian Penal Code, 1860
2. Income Tax Act, 1961
3. Civil Services (Conduct) Rules, 1964
4. All India Services (Conduct) Rules, 1968 (the Service Rules)

5. Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA).
6. CVC Act 2003
7. Foreign Contribution Regulation Act, 2010 (FCRA)
8. Whistle-Blowers Protection Act, 2011
9. Lokpal and Lokayuktas Act, 2013
10. Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015
11. CAG
12. Enforcement Directorate

केंद्रीय सतर्कता आयोग

भारत में राष्ट्रीय स्तरपर भ्रष्टाचार विरोधी तीन प्रमुख संस्थाएं (केंद्रीय जांच ब्यूरो, लोकपाल तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग) है जिसमें से केंद्रीय सतर्कता आयोग एक मुख्य शीर्षस्थ संस्था है। यह समस्त कार्यकारी प्राधिकारी के जवाबदेही से मुक्त तथा संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यह केंद्र सरकार के तहत आने वाली सभी सतर्कता गतिविधियों पर नज़र रखता है। केंद्रीय सरकारी संगठनों के लिए यह सलाहकार की भूमिका भी निभाता है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग को एक ऐसी संस्था के रूप में नामित किया गया है जो रिश्वतखोरी, कार्यालयों के दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतों को सुनता है तथा उनपर त्वरित रूप से उचित कार्रवाई की सिफारिश भी करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास केंद्र सरकार, लोकपाल तथा मुखबिर/सूचना प्रदाता/सचेतक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह आयोग वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अपने किए गए कार्यों तथा उन प्रणालीगत विफलताओं का विवरण देती है जिनके फलस्वरूप विभागों में भ्रष्टाचार पनप रहा है।

2003 में इंजीनियर श्री सत्येंद्र दुबे की हत्या के उपरान्त सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के आधार पर, पद के दुरूपयोग तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत प्राप्त करने तथा कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को एक नामित संस्था के रुप में प्राधिकृत किया गया। इसे सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचना प्रदाता संरक्षण संकल्प (Public Interest Disclosure and Protection of Informer resolution -PIDPI) के तहत शिकायतकर्ता से संबंधित जानकारी को गुप्त रखने की ज़िम्मेदारी भी सौपी गई। इसके बाद सरकार ने अन्य विधानों तथा अधिनियमों के माध्यम से समय – समय पर आयोग की शक्तियों तथा कार्यों में वृद्धि की है।

हमारे देश में भ्रष्टाचार की स्थिति काफी बदतर कही जा सकती है | सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में एवं आम आदमी को राहत प्रदान करने में भ्रष्टाचार मुख्य बाधा है | भ्रष्टाचार निरोधी विभिन्न विभाग एवं संस्थाएं विगत वर्षों से रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान छेड़े हुए हैं | फोरेंसिक जांच एवं अन्य नवीनतम तकनीक का प्रयोग न्यायालयों में अपराध सिद्ध करने में सहायक हो रहे हैं | किन्तु संविधान की भावना को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए कानूनों को और अधिक सक्रियता से लागू करने की आवश्यकता है |

हरदेव पन्त
उप महाप्रबंधक (सतर्कता)
ऋषिकेश

"भ्रष्टाचार मुक्त भारत - विकसित भारत"

प्रत्येक देश अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता तथा चरित्र के कारण पहचाना जाता है। भारत, उच्च नैतिक मूल्यों, नैतिकता, मानवतावादी गुणों और परंपराओं का देश है जहाँ चरित्र और त्याग को सर्वोतम माना गया ।श्रीमद् भगवद्गीता में कहा गया है -

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ।।

काम, क्रोध, और लोभ, ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के तीन दरवाजे हैं, अतः इन तीनो को त्याग देना चाहिए। वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो, न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरूद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है, वह भ्रष्टाचार की परिसीमा में है। चरित्रशील, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, त्याग, राष्ट्र प्रेम, सेवा भाव, सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के बिना भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण सम्भव नही ।

भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाये रखने के लिए आवश्यक है:

शिक्षा का प्रसार : शिक्षा का अभाव मुख्य कारणों में से एक है। अशिक्षित वर्ग से जुड़े कई लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए अवैध और भ्रष्ट तरीकों का इस्तेमाल न करें। शिक्षा ही इस समस्या को काफी हद तक कम करने में मदद कर सकती है। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाना चाहिए कि देश में हर बच्चा स्कूल जाए और शिक्षा हासिल करे।

रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना: नौकरी योग्य युवाओं की संख्या की तुलना में कम है ।कुछ युवाओं को नौकरी उनकी योग्यता के बराबर नहीं मिलती जिस कारण असंतोष और अधिक कमाई का लालच भ्रष्ट तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। आर्थिक सुधार, औधोगिक नीति में परिवर्तन और उपलब्ध संसाधनों के उपयोग से बेरोजगार और निर्धनता की समस्या को कम करता है तथा रोजगार के सुअवसर उपलब्ध होते है।

पारदर्शी नागरिक अनुकूल सेवाएँ: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पहल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से सरकार की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरीद में ई-निविदा, ई-गवर्नेंस की शुरुआत, प्रक्रिया व् प्रणालियों का सरलीकरण में भ्रष्टाचार को लगाम लगेगा।

सख्त कानून व्यवस्था : व्यवस्थागत सुधार एवं सख्त कानून व्यवस्था से जनमानस में भ्रष्टाचार को लेकर पैदा हुए हताशा के वातावरण को बदल कर भरोसे का माहौल निर्मित करता है। अच्छे कार्य की सराहना और बुरे कार्यों में उचित दंड का समन्वय हो।

प्रौद्योगिकी एवं मीडिया की भूमिका: सरकारी कार्यालयों, सड़क चौराहों व अन्य जगहों पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने तथा मीडिया को नियमित रूप में स्टिंग ऑपरेशन करने से भ्रष्ट तरीकों का उपयोग नही होगा ।

सतर्कता, सूचना का अधिकार की भूमिका: भ्रष्टाचार एक अपराध है और इसके खिलाफ लड़ने के लिए सभी को उचित कदम उठाने चाहिए। भ्रष्टाचार लाभ कमाने का अनुचित और अनैतिक साधन है। समाज में सभी वर्गों को हमारे राष्ट्रीय जीवन में ईमानदारी बनाए रखने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है ।हर स्तर पर सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार से लड़ने का एक बड़ा हथियार है।

विकसित देश की अभिकल्पना:

"सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्"

सभी सुखी होवें, सभी रोगमुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बनें और किसी को भी दुःख का भागी न बनना पड़े। हर एक व्यक्ति भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहता है। नैतिक मूल्यों को शीर्ष में रखते हुए हर व्यक्ति को दृढ़ निश्चय कर लेने पर कोई भी कार्य कर पाना असम्भव नही, आवश्यकता है सतर्कता एवं जागरूकता, सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार निवारण कानूनों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करना, जिससे विकसित भारत भ्रष्टाचार क्षेत्र में ईमानदार, पारदर्शी और जवाबदेह बना रहे।

दिनेश चन्द्र भट्ट
उप महाप्रबंधक (विद्युत),
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, टिहरी

परिवार से परिवर्तन

घूस न लेंगे, घूस न देंगे,
हम सबका नारा होगा।
भ्रष्टाचार मिटाना हमको,
और सुशासन लाना होगा।

सबसे पहले अपने घर में
यह परिवर्तन लाना होगा।
निज जीवन में सरल, सुगमता,
आदर्श आचरण अपनाना होगा,
शिशु जैसा भोलापन लेकर,
कर्तव्य पथ पर जाना होगा,
बच्चों के पालन-पोषण में,
सहज सादगी लाना होगा,
उनकी अनजानी मांगों को,
नाजायज ठहराना होगा।

भ्रष्ट राह पर कोई भी हो,
उसको भय दिखलाना होगा,
पथभ्रष्ट हो चुके इंसानों को,
सही मार्ग पर लाना होगा,
परिवार सबल होगा तब ही,
थोड़े में गुजारा करना होगा,
स्वस्थ और सुंदर जीवन का,
समावेश जन-जन में होगा,
परिवार सशक्त होंगे तो,
राष्ट्र स्वयं शक्तिशाली होगा।

घूस न लेंगे, घूस न देंगे,
हम सबका नारा होगा ।
भ्रष्टाचार मिटाना हमको,
और सुशासन लाना होगा ।

पंकज कुमार शर्मा
उप प्रबंधक (राजभाषा)
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश

भ्रष्टाचार मुक्त भविष्य

भ्रष्टाचार अर्थात भ्रष्टआचार। भ्रष्टाचार केवल रिश्वत लेने या देने का नाम नहीं है। जो व्यवहार सामाजिक मूल्यों के अनुसार नहीं है, वही भ्रष्टाचार है जैसे झूठ बोलना, धोखा देना, किसी को नीचा दिखाना, ईर्ष्या करना और रिश्वत लेना व देना दोनों ही, ऐसे अनगिनत उदाहरण है तथा सभी व्यक्ति इससे भली भांति परिचित भी हैं परन्तु प्रश्न यह है कि इस भ्रष्टाचार को, जिसने न केवल हमारे भारतवर्ष अपितु विश्व के कई अन्य देशों को अपनी गिरफ्त में लपेट रखा है, को कैसे दूर किया जाए। चूँकि भ्रष्टाचार व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित है अतः इसका उपचार भी व्यावहारिक ही होना चाहिए। मनुष्य जब जन्म लेता है, तो कहते हैं कि वह निष्पाप एवं मासूम होता है परन्तु समय के अनुसार उसमें ये सब दोष घर कर जाते हैं। अत: आवश्यकता है एक ऐसी शिक्षा पद्धति की जो प्रारंभ से ही व्यक्ति में मानव मूल्यों की नींव रख सके। कुछ दशक पहले सभी विद्यालयों में नैतिक शिक्षा नामक एक विषय होता था जिससे हमारे पूर्वजों एवं महापुरुषों की अनगिनत सद-मूल्यों की व्याख्या इस ढंग से की जाती थी कि वो बच्चों के मस्तिष्क पर अंकित हो जाती थी। फिर ना जाने यह नैतिक शिक्षा कहाँ गायब हो गई और उसकी जगह एक ऐसी प्रणाली ने ले ली जो आपसी मनमुटाव, वैमनस्य एवं ईर्ष्या जैसे व्यवहार को बढ़ावा देती है। आजकल तनाव भरे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपना अस्तित्व बचाने हेतु निरंतर प्रयत्नशील है और उसके लिए वह अपने नैतिक मूल्यों को भी दांव पर लगा देता है। निष्कर्ष यह है कि हमारी शिक्षा पद्धति में फिर से ऐसा बदलाव किया जाना आवश्यक है कि बच्चा, बचपन से ही ईमानदार एवं सच्चा जीवन जीने की कला सीख लें और जब अपनी शिक्षा समाप्त होने पर समाज एवं देश की सेवा के लिए निकले तो वह एक ऐसी वीर की भाँति व्यवहार करें जिसमें न तो कपट हो और ना ही भ्रष्ट आचार।

मेरा मानना है कि हमारे विद्यालयों में नैतिक शिक्षा प्राथमिक स्तर से ही अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जानी चाहिये जिससे कि आने वाली पीढ़ी के शब्दकोश में भ्रष्टाचार नामक शब्द ही ना हो और वे भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण में साँस ले सके

उषा गर्ग पत्नी श्री मुकुल गर्ग
(उप महा प्रबंधक, मोनिटरिंग)
ऋषिकेश

भ्रष्टाचार मुक्त विकसित भारत: एक सोच बदलाव की

प्रस्तावना :-

भारत एक उच्च मूल्यों और नैतिक परम्पराओं वाला देश है, लेकिन इसके समक्ष एक सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है जो विभिन स्तरों पर देखने को मिल रही है। यह एक ऐसी समस्या है जो देश को आंतरिक रूप से नुकसान पहुंचा रही है जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारे देश पर पड रहा है। यह किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। चाहे राजनीति हो, चाहे प्रशासन, या कोई विभाग, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कार्य किये जा रहें हैं लेकिन भ्रष्टाचार का मुख्य कारण अशिक्षा है। सिर्फ सरकार के प्रयासों से हम भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकते। इसके लिए आज के युवाओं को, राजनेताओं को और उन सभी व्यक्तियों को आगे आना चाहिए, जो इससे पीड़ित हैं। भारत एक लोकताचिक देश है। जब भी यहाँ चुनाव होते हैं, तो इनमें राजनितिक दलों केनेताओं हेतु कोई भी शैक्षणिक योग्यता या मानदंड निर्धारित नहीं है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमें योग्य नेता का चुनाव करना बेहद जरुरी है, जो शिक्षित हो। लोगों को जागरूक किया जाये कि भ्रष्टाचार क्या है, और इससे कैसे निपटा जाये। हम सबको भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए अपना योगदान देना होगा। जिसके लिए हमें स्वयं को और अपने आस-पास के लोगों को शिक्षित करना होगा।

भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार :-

भ्रष्टाचार पूरे देश में बीमारी की तरह फैल रहा है यदि समय रहते भ्रष्टाचार को रोका नहीं जायेगा तो पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लेगा। हमारे भारत देश में जो अशिक्षित लोग हैं वो तो भ्रष्टाचार की चपेट में आते हैं परन्तु जो पड़े लिखे लोग हैं वो भी भ्रष्टाचार में साथ देते है और कई व्यक्ति नौकरी की अच्छी पोस्ट पाने के लिए रिश्वत देने में नहीं चूकते हैं और लोग रिश्वत लेते भी हैं। वर्तमान में देश भर में सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रष्टाचार की ख़बरों को काफी उजागर किया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को नौकरी देने का झांसा दिला कर लोग उनसे पैसे लूट लेते हैं। देश भर में आये दिन इस प्रकार के केस देखने को मिलतें हैं। देश में जितने भी सरकारी कार्य होते हैं उनमें कहीं न कहीं प्राय: भ्रष्टाचार देखने को मिलता है।

भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय :-

समाज में विभिन्न स्तरों पर फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमें एक साथ जुट होकर सामना करना चाहिए, जो लोग रिश्वत लेते समय पकड़े जाते हैं, वहीं व्यक्ति रिश्वत देकर छूट भी जाते हैं। रिश्वत देने और लेने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ताकि भारत में बीमारी की तरह फ़ैल रहा भ्रष्टाचार को रोका जा सके । भारत में अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे लोग भ्रष्टाचार से बच सकें।

भ्रष्टाचार विरोधी दिवस :-

दुनिया भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में जागरूकता फ़ैलाने के लिए ही ९ दिसम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ३१ अक्टूबर २००२ को एक प्रस्ताव पारित कर अन्तर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाने की घोषणा की।

निष्कर्ष:-

भ्रष्टाचार से जुड़े लोग अपने स्वार्थ के लिए देश का नाम ख़राब कर रहें हैं। हम सबको भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने होंगे, तभी हम भारत को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला कर, भारत को विकसित कर सकते हैं। इस कदम में शिक्षा तथा अच्छे नैतिक मूल्य एवं संस्कार निश्चित ही मील का पत्थर साबित होंगे।

"जय हिन्द, जय भारत"

(दिलीप कुमार द्विवेदी)
वरिष्ठ प्रबंधक (मा०स०एवं प्रशा)
टिहरी

" भ्रष्टाचार मुक्त भारत - विकसित भारत"

यदि विकसित करना है भारत को,
भ्रष्टाचार मिटाना होगा ।
यदि प्रगति की राह पर चलना है हमको,
यह पहला कदम बढ़ाना होगा ।।

भ्रष्टाचार है एक दीमक जैसा,
जो अन्दर-अन्दर खा जाता है।
जिस देश में भ्रष्टाचार व्याप्त हो,
वो कभी पनप नहीं पाता है ।।

हजारों उदाहरण हैं दुनिया में,
भ्रष्टाचार से हुई बर्बादी के ।
अपने पड़ोसी मुल्कों को ही ले लो,
बुरे हाल हैं इनकी आबादी के ।।

यदि अपने भारत को हमको,
विकसित और समृद्ध बनाना है ।
सबसे पहले देश को 'अमर '
भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है ।।

अमर कुमार भारतीय
उप प्रबंधक (एस.बी./संचि. एवं सा.प्रबं.)
एसटीपीपी, खुर्जा

खुदगर्जी

एक लम्बा सफर तय किया है
पर सफर अभी तमाम बाकी है।
दरख्त तो उग चुका है
पर शाखाओं पर फूल खिलना बाकी है।

कोशिशों से सीखा है बहुत कुछ,
उम्मीदों से खुदको जगाया है,
अब अपनी अलख से,
भटके हुए कुछ और लोगों को जगाना बाकी है।

खुदगर्जी का पानी सिर से ऊपर निकल गया,
लालच ने हमको पूरा का पूरा भर दिया,
अपने खुद के शौक देखे ता-उम्र,
अब किसी गरीब का दर्द समझना बाकी है।

हर काम का दाम ले लिया,
बेगैरत ने सब जगह ले लिया,
अपनी ही कब्र पर खड़ा इन्सां,
बस अपनी रूह से रिश्वत लेना बाकी है।

सुशील कुमार
वरिष्ट अभियन्ता, केन्द्रीय भण्डार,
टिहरी

भ्रष्टाचार मुक्त भारत - समृद्ध भारत

खत्म हो गई सद्भावना, गुम हो गया सुविचारों का दौर,
धोखे और भ्रष्टाचार की लूट, मची है चारों ओर,
नहीं देश की फ़िक्र किसी को, नहीं किसी का कोई उसूल,
ईमानदारी घोल पी गए, सब करने लगे हैं पैसा वसूल।

भ्रष्टाचारियों ने इस दीवार को इतना मजबूत बनाया है,
कि हर वर्ग ने भ्रष्टाचार को अपना हथियार बनाया है।
आसानी से काम निकालने का जरिया बनाया है,
किसी ने उपहार, तो किसी ने सुविधा शुल्क बताकर इसे आसान बनाया है।

यह कसूर नहीं होगा, उन भ्रष्टाचारियों का अब जनता को निर्णय लेना है
आने वाली पीढ़ियों को भ्रष्टाचार मुक्त समाज देना है
रोकना है इस छूत की बीमारी को, अन्यथा यह सब नष्ट कर देगी
दीमक की तरह लगकर, पीढ़ियों में भी किसी को नहीं छोड़ेगी।

बह रहा है जो रक्त नसों में, उसे शुद्ध करना होगा,
भ्रष्टाचार की दीमक से देश को मुक्त करना होगा,
भ्रष्टाचार मुक्त भारत, का सपना साकार करना होगा,
प्रत्येक भारतवासी को इस प्रयास में अपना योगदान देना होगा।

गणेश मिश्रा
वरि प्रबंधक (ओ.एड.एम.)
कोटेश्वर

भ्रष्टाचार मुक्त भारत

भ्रष्टाचार मुक्त भारत में रहना
हर भारतीय का है यह सपना।
आओ मिलकर सब प्रण करें
भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करें।
भ्रष्टाचार की फैली यह महामारी
हर एक को है रिश्वत लेने-देने की बीमारी।
मिलकर इसको दूर भगायें
भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनायें।

नया सवेरा लायेगें हम
हमने मन में ठाना है।
भ्रष्टाचार और घूसखोरी को
सतर्कता से हटाना है।

सतर्क प्रहरी हम भारत के
भारत का गौरव बढ़ायेंगें।
फिर से नया सवेरा होगा
सोने की चिड़िया कहलायेगें |

रूचि रावत
प्रशिक्षु कोपा,
सतर्कता विभाग, टिहरी

भ्रष्टाचार मुक्त भारत - विकसित भारत

(Corruption Free India for a Developed Nation)

"हर तरफ कानून की कतारें है मगर,
हर तरफ एक चोर रास्ता है हमारे देश में।"

भ्रष्टाचार एक ऐसा अनैतिक आचरण है जिसमें व्यक्ति खुद की छोटी-छोटी इच्छाओं की पूर्ति हेतु देश को संकट में डालने में भी तनिक देर नहीं करता है। देश के भ्रष्ट नेताओं व अधिकारियों द्वारा किया गया घोटाला ही भ्रष्टाचार नहीं कहलाता बल्कि एक ग्वाले द्वारा दूध में पानी मिलाना भी भ्रष्टाचार ही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (Transparency International) एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसके द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर विभिन्न देशों की रैंकिंग मापी जाती है। इस संस्था का मानना है कि "शक्ति का दुरुपयोग करना भी भ्रष्टाचार है"।

यदि आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके साथ आपको शक्ति भी मिलती है, जिसका उपयोग आपको जनकल्याण के लिए करना है किंतु उसका उपयोग सही जगह पर ना करके यदि दूसरों को परेशान करने के लिए करेंगे तो यह भ्रष्टाचार कहलाएगा, यानी भ्रष्ट आचरण। पिछले वर्ष आपने सुना होगा की इंदौर शहर स्वच्छता के मापदंडों में प्रथम स्थान पर आया है, इसका कारण है वहां के जिम्मेदार व सजग अधिकारी एवं जागरूक जनता। इंदौर के विषय में मैंने पढ़ा था कि वहां पर गलत जगह पड़े कूड़े के ढेर में एक टिशु पेपर पड़ा मिला, उस टिशु पेपर पर होटल का नाम अंकित था। स्वच्छता निरीक्षक/अधिकारी उसी वक्त उस होटल पर गए, जिसका नाम उस टिशु पेपर पर था और होटल मालिक पर ₹ 50,000 का जुर्माना लगा दिया। इस प्रकार जुर्माने से जो रकम मिलती है वह शौचालय, पार्कों आदि की देखरेख में लगाई जाती है। यदि सभी संबन्धित अधिकारीगण सतर्कता, ईमानदारी व जागरूकता से कार्य करेंगे, तो जनता स्वयं ही जागरूक होगी ओर भारत, विकसित देशों की तरह ही विकसित भारत कहलाएगा।

भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम: 2018 में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है वह व्यक्ति भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। मान लीजिए आपका चयन संघ लोक सेवा आयोग में हो जाता है तो आपको जनता की सेवा करने व अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए चयनित किया गया है। आपका चयन जनता के कल्याण के लिए किया जाता है यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य व उनके अधिकारों का हनन ही नहीं करते बल्कि आप उनके जीवन तक का नाश करते हैं।

भ्रष्टाचार के लिए सिर्फ अधिकारी वर्ग ही नहीं, बल्कि जनता भी जिम्मेदार होती है जैसे रिश्वत लेने वाला जितना गुनहगार है उतना ही देने वाला भी गुनहगार है। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि भारतीय राजनीति भ्रष्ट है, लेकिन यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां भ्रष्टाचार निहित है। भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में मौजूद है और यह हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। घर बनाते समय अपनी पूरी जगह घेर कर रैंप को बाहर सड़क पर निकालना, घरों के छज्जे बाहर निकालना, सड़कों पर बनी नालियों को दबाकर उस पर निर्माण कर देना भी भ्रष्टाचार ही है।

यदि अधिकारी अपने अधिकारों का ईमानदारी व सतर्कता से पालन करें तो जनता भी सजग व सतर्क रहेगी और जब जनता जागरूक हो गई तो भ्रष्टाचार जैसी बीमारी का सर्वनाश हो ही जाएगा। भ्रष्टाचार फैलने का सबसे ज्यादा उदाहरण हमारी भारतीय राजनीति में निहित है। ऐसा माना जाता है कि यहां पर कोई भी व्यक्ति चाहे वह अशिक्षित व अपराधी प्रवृत्ति का ही क्यों न हो, चुनाव लड़ सकता है। अब आप ही सोचिए एक अशिक्षित व अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति समाज को क्या दे सकता है। वह अपराधियों को ही तो बढ़ावा देगा। एक शिक्षित व साफ-सुथरी छवि वाला व्यक्ति ही देश को अच्छे माहौल के साथ-साथ विकास की ओर ले जा सकता है। इसके साथ ही यदि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो रिश्वतखोरों, गैरकानूनी तरीके से व्यवसाय करने वालों, काला धन कमाने वालों व देश की प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाने वालों को सख्त से सख्त और तुरंत सजा देनी चाहिए ताकि अन्य लोगों को सबक मिल सके तभी हमारा भारत भ्रष्टाचार मुक्त वह विकास के रास्ते पर अग्रसर हो सकेगा।

अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि यदि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त व विकसित भारत बनाना है तो सरकार, राजनीतिक दलों तथा नागरिकों के लिए एक उदाहरण तैयार करना होगा और भ्रष्ट तरीकों से काम करने की बजाय अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ईमानदारी व समर्पण से कार्य करने के लिए प्रेरित करना होगा। हमारे देश को इस बुरी प्रथा से मुक्त करने के लिए सरकार व जनता सभी को एकजुट होना होगा और अपने प्रयासों में ईमानदारी को शामिल करना होगा, तभी हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत व विकसित भारत का निर्माण कर सकेंगे।

नीलम चमोली काला
शिक्षिका एवं समाज सेविका,
w/o श्री राजेश चमोली,
वरि. प्रबन्धक (परिकल्प-सिविल),
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश।

भ्रष्टाचार मुक्त भारत - विकसित भारत

आओ वचन निभाते हैं,
भ्रष्टाचार मिटाते हैं।
देश को विकसित करते हैं,
अपनी छवि बनाते हैं।।

भ्रष्टाचार के दल-दल ने,
हम सबको ले डुबाया है।
भारत माँ के सीने को,
भ्रष्टाचारियों ने दु:खाया है।।

कोई काम यहां नहीं बनते,
दर-दर लोग भटकते हैं।
काम उन्हीं के बनते हैं,
जो भ्रष्टाचार कर पाते हैं।।

गरीब, बेवस लाचार की तो,
बस आह निकलती जाती है।
बिना घूस-रिश्वत दिये तो,
काम अधूरे रह जाते हैं।।

भ्रष्टाचार की आग की लपटें,
जो हम तक पहुंचाएगा।
दमन हम उसका कर बैठेंगे,
कोई उसे बचा न पायेगा।।

भ्रष्टाचार की आग लगी है,
भारत की इन गलियों में।
ईमानदारी का पाठ पढ़ाकर,
अपनी पहचान बनाएगें।।

आओ संकल्प करें हम सारे,
भ्रष्टाचार मिटायेंगे।
ना खुद भ्रष्टाचार करेंगे
ना भ्रष्टाचार करवाएगे।।

ईमानदारी का दर्पण बनकर,
हम सच्ची राह दिखाएगे।
भारत को विकसित करके,
नया भारत बनाएंगे।।

डॉ. राजेश्वरी व्यास
163, राजेश्वरीपुरम, देहरादून।
माता श्री सचिन व्यास
प्रबंधक (ओ एंड एम),टिहरी

सतर्कता जागरूकता सप्ताह
VIGILANCE AWARENESS WEEK

31st October - 06th November, 2022

''भ्रष्टाचार मुक्त भारत-विकसित भारत''

"Corruption free India for a developed Nation"

सतर्कता विभाग, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
Vigilance Department,THDC India Limited

सतर्कता जागरूकता सप्ताह
VIGILANCE AWARENESS WEEK

31st October - 06th November, 2022

''भ्रष्टाचार मुक्त भारत–विकसित भारत''

"Corruption free India for a developed Nation"

सतर्कता विभाग, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
Vigilance Department,THDC India Limited

सतर्कता जागरूकता सप्ताह
VIGILANCE AWARENESS WEEK

31st October - 06th November, 2022

''भ्रष्टाचार मुक्त भारत-विकसित भारत''

"Corruption free India for a developed Nation"

सतर्कता विभाग, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
Vigilance Department,THDC India Limited

GENERATING POWER
TRANSMITTING PROSPERITY

Drinking Water to Millions

300 cusecs (162 MGD)
of Drinking Water for **Delhi** to meet the requirement of about
40 lakh population

200 cusecs (108 MGD)
of Drinking Water for towns and villages of **Uttar Pradesh** to meet the requirement of about
30 lakh population

लाखों लोगों के लिए पीने का पानी

300 क्यूसेक (162 मिलियन गैलन प्रतिदिन)
दिल्ली के लिए पीने का पानी, लगभग **40 लाख** लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए

200 क्यूसेक (108 मिलियन गैलन प्रतिदिन)
उत्तर प्रदेश के नगरों एवं गाँवों के लिए
पीने का पानी, लगभग **30** लाख लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED
(श्रेणी–'क', मिनी रत्न, उपक्रम)
(SCHEDULE-'A',Mini Ratna, PSU)

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

Ganga Bhawan, Pragatipuram, By-Pass Road, Rishikesh-249201- Uttarakhand)
(Schedule-A Mini Ratna, Government PSU)

(इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों/रचनाओं में व्यक्त किये गये विचार लेखकों के अपने है,
और उनसे टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड प्रबंधन का सहमत होना आवश्यक नहीं है।)